Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

‘भारतीय संस्कृति और योग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक अलग पहचान दिलाई है’

वर्ष-21, अंक-12 16-30 जून, 2026 (पाक्षिक) ₹20

12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

‘योग हम सभी को जोड़ता है और हमें एक साथ लाता है’

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 21 जून, 2026 को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जालंधर (पंजाब) में 21 जून, 2026 को आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में सम्मिलित होते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन

शिलांग (मेघालय) में 21 जून, 2026 को ईस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर में भारतीय वायु सेना एवं भारतीय सेना के जवानों के साथ 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग सत्र में भाग लेते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

अहमदाबाद (गुजरात) में 21 जून, 2026 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में योगाभ्यास करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

शांति पथ (नई दिल्ली) पर 21 जून, 2026 को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग-प्रेमियों के साथ योगाभ्यास करते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 19 जून, 2026 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फाउंडेशन के पुनर्निर्मित कार्यालय का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

सहायक संपादक
विपुल शर्मा
राजीव कुमार

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

प्रसार एवं सदस्यता
अमित सक्सेना

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

Scan to Download
www.kamalsandesh.org

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

विषय-सूची

06 प्रधानमंत्री ने कोलकाता से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का किया नेतृत्व

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन...

08 भारतीय संस्कृति और योग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक अलग पहचान दिलाई है: नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 21 जून, 2026 को पंजाब...

10 प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत ने जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री...

13 प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा...

30 प्रधानमंत्री ने फ्रांस व स्लोवाकिया की सफल यात्रा की और जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों और...

लेख

भारतीय जनसंघ ही क्यों? / **डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी** 14
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से 'भारतीयता में विश्वास' तक / **राम नाथ कोविंद** 16
पीएमएसएमए का एक दशक: मातृ स्वास्थ्य का कायाकल्प और सुरक्षित मातृत्व की ओर भारत के तेजी से बढ़ते कदम / **जगत प्रकाश नड्डा** 18
मोदी की यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एवं पारदर्शिता का प्रतीक है / **नीतीश कुमार** 20
भारत ने श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई के लिए खाड़ी देश में अवसरों के द्वार खोले / **पीयूष गोयल** 22
पीएम स्वनिधि योजना: पथ विक्रेताओं के सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन की परिवर्तनकारी यात्रा / **मनोहर लाल खट्टर** 24
भारत का सांस्कृतिक पुनरोद्धार काल / **गजेन्द्र सिंह शेखावत** 26
मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो किसान समृद्ध, गांव खुशहाल और देश सुखी रहेगा / **भजनलाल शर्मा** 28

अन्य

योग केवल स्वस्थ शरीर का आधार नहीं है, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन जीने का मार्ग है: राजनाथ सिंह 09
योग मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार है: अमित शाह 09

नरेन्द्र मोदी

'राष्ट्र प्रथम' की भावना हमारे लिए सर्वोपरि रही है, इसलिए हम बेहद सधे तरीके से असंभव समझे जाने वाले कई निर्णय भी ले पाए हैं। देशहित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।

(10 जून, 2026)

नितिन नवीन

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प के साथ, आज देश के सभी राज्यों के विकास, सम्मान, विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

(02 जून, 2026)

राजनाथ सिंह

हमारी नियत बिल्कुल साफ है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जिन-जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां सभी अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी यह काम शुरू हो चुका है। हम अगले Election की नहीं, बल्कि अगली Generation की चिंता करते हैं।

(12 जून, 2026)

अमित शाह

मोदी जी का नेतृत्व संकल्प से सिद्धि और सेवा से सुशासन की यात्रा का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में भारत ने आत्मविश्वास, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए मानदंड स्थापित किए हैं।

(10 जून, 2026)

जगत प्रकाश नड्डा

'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के 10 वर्ष पूरे होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों के स्वास्थ्य विभागों और सभी संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस दूरदर्शी पहल को एक सफल जनकल्याणकारी अभियान के रूप में स्थापित किया है।

(09 जून, 2026)

बी.एल. संतोष

वह पार्टी जो अपने साथी 'मुस्लिम लीग' को खुश करने के लिए काफी हद तक झुक जाती है, उसे कुछ उप-कुलपतियों की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अपना राष्ट्रवादी चरित्र दिखाया है, जिससे आप कुर्सी के मोह और अपने बॉस के डर से डरते हैं।

(19 जून, 2026)

योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है

दुनिया ने वर्ष 2026 में 'हेल्दी एजिंग फॉर योग' (स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग) थीम के साथ 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग विश्वभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और आधुनिक जीवनशैली की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऐतिहासिक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद पिछले बारह वर्षों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसे नए भारत का सशक्त प्रतीक बन गया है, जो 'विकास और विरासत' के दृष्टिकोण को आत्मसात् करता है, अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करता है और अपने प्राचीन ज्ञान को विश्व के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सांस्कृतिक पुनर्जागरण, वैश्विक नेतृत्व तथा एक स्वस्थ और अधिक सामंजस्यपूर्ण मानवता के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही, यह सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण (वेलनेस) को सुलभ बनाने की भारत की अवधारणा को भी साकार करता है। गंगा के तटों से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक, योग एक वैश्विक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है और 21वीं सदी में भारत की सभ्यतागत कूटनीति की सबसे स्थायी एवं प्रभावशाली विरासतों में से एक बन गया है।

वर्ष 2014 में, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विश्व के समक्ष भारत की महानतम सांस्कृतिक धरोहरों में से एक 'योग' को प्रस्तुत किया, तब एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। सदियों पुरानी यह परंपरा मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम मानी जाती है। योग समग्र विकास, प्रकृति के साथ सामंजस्य, रोगों की रोकथाम तथा भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना का सशक्त प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, तो उसे अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह-प्रायोजन किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक समर्थन प्राप्त प्रस्तावों में से एक था। तब से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और 'सॉफ्ट पावर' (सांस्कृतिक प्रभाव) के विस्तार का सबसे सफल उदाहरण बनकर उभरा है। यह भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है, जो आज भी आधुनिक विश्व में उतनी ही प्रासंगिक हैं। योग न केवल स्वास्थ्य, खुशहाली और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है, बल्कि यह देशों, संस्कृतियों और समुदायों को जोड़ने वाले एक सशक्त सेतु के रूप में भी कार्य करता है। इसी कारण योग आज मानवता के साझा कल्याण और वैश्विक एकता का प्रतीक बन चुका है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि योग केवल एक प्राचीन भारतीय परंपरा नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन का ऐसा सार्वभौमिक मार्ग है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर वैश्विक मंच पर भारत की 'ग्लोबल ग्रोथ इंजन' के रूप में उभरती भूमिका को और अधिक मान्यता एवं स्वीकार्यता दिलाई। एक साझेदार देश के नेता के रूप में आमंत्रित प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को प्रभावी ढंग से विश्व समुदाय के समक्ष रखा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विकास वित्तपोषण व्यवस्था में सुधार तथा वैश्विक निर्णय-निर्माण संस्थाओं में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक लचीलापन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी सक्रिय भागीदारी ने 21वीं सदी की चुनौतियों के समाधान में भारत की बढ़ती और रचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अनेक प्रमुख वैश्विक नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन संवादों ने भू-राजनीतिक चुनौतियों और मतभेदों के बीच भारत की एक विश्वसनीय साझेदार, संवादकर्ता और सेतु-निर्माता राष्ट्र के रूप में स्थापित भूमिका को और सुदृढ़ किया। वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय एजेंडा निर्धारण और वैश्विक नीति-निर्माण में भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, रणनीतिक प्रभाव तथा एक समावेशी, न्यायपूर्ण, स्थिर और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आज, जब हम वर्ष 2015 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित पहले 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' को याद करते हैं— जिसने एक वैश्विक जन-आंदोलन के रूप में विश्व स्तर पर कई रिकॉर्ड स्थापित किए थे— तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि योग के प्रति लोगों की भागीदारी और उत्साह निरंतर बढ़ता गया है। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिवर्ष 190 से अधिक देशों के लाखों लोगों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में भाग लिया है। योग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों, शैक्षणिक संस्थानों, जन-जागरूकता अभियानों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न प्रयासों का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और कल्याण (वेलनेस) के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका और अधिक सुदृढ़ हुई है। साथ ही, योग 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। वेलनेस पर्यटन, अनुसंधान, योग शिक्षक प्रशिक्षण तथा पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उद्योगों के माध्यम से यह भारत की अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। इससे नए रोजगार और अवसर सृजित हो रहे हैं तथा विश्वभर में भारत की सांस्कृतिक पहचान और प्रभाव को भी नई मजबूती मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि योग केवल एक प्राचीन भारतीय परंपरा नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन का ऐसा सार्वभौमिक मार्ग है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

योग हम सभी को जोड़ता है और हमें एक साथ लाता है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने हजारों योगाभ्यासियों के साथ 'साझा योग नियम' सत्र में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनियाभर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21 जून दुनिया के कई हिस्सों में साल का सबसे लंबा दिन होता है और यह योग के ज़रिए मानवता के सबसे बड़े सामूहिक उत्सवों में से एक के रूप में भी उभरा है।

पूरा देश योग की भावना से ऊर्जावान

कोलकाता में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से योग की प्रेरणादायक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। श्री मोदी ने कहा, "हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और बंगाल तथा पूर्वोत्तर से लेकर सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र तक पूरा देश योग की भावना से ऊर्जावान लग रहा है। देश और दुनिया स्वास्थ्य और सामंजस्य के साझा संकल्प के माध्यम से जुड़ी हुई लगती हैं, जो योग की एकता की शक्ति को प्रतिबिंबित करती है।"

प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छता से स्वागत' पहल के तहत कोलकाता के लोगों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि साफ़-सफ़ाई बनाए रखने में नागरिकों ने जो लगन, कड़ी मेहनत और नागरिक ज़िम्मेदारी दिखाई है, वह देश भर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है।

श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में योग दिवस का आयोजन खास महत्व रखता है, क्योंकि राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। उन्होंने याद दिलाया कि बंगाल वह भूमि है, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस रहे थे और शिक्षा दी थी, जहां से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और योग परंपराओं से परिचित कराया था और जहां महर्षि अरबिंदो और लाहिड़ी महाशय ने योग के विचारों और अभ्यास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की शिक्षाओं का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की असली पहचान हमारे आस-पास की दुनिया के साथ सार्थक संबंधों

से बनती है और यही सिद्धांत योग के मूल में है। उन्होंने महर्षि अरबिंदो की इस बात का भी ज़िक्र किया कि पूरा जीवन ही योग है; उन्होंने कहा कि जब योग किसी के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, तो यह मानवीय एकता की आधारशिला को मजबूत करता है।

योग चेतना, जीवन-शक्ति और आंतरिक प्रकाश का स्रोत है

श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा, "योग केवल शारीरिक व्यायाम का एक रूप नहीं है और इसे किसी खास आयु-वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह चेतना, जीवन-शक्ति और आंतरिक प्रकाश का स्रोत है, जो मानव जीवन के हर पड़ाव को समृद्ध बनाता है।" इस साल के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बने रहने का रास्ता दिखाता है।

श्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ आयु का मतलब इस बात को सुनिश्चित करना है कि बढ़ती उम्र के साथ मानव क्षमता कम न हो। उन्होंने कहा कि योग पूरे जीवन में लगातार विकास और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने यह कामना व्यक्त की कि लोग बीस साल की तुलना में चालीस साल की उम्र में अधिक लचीले हों, तीस साल की तुलना में पचास साल की उम्र में अधिक ऊर्जावान हों और पचास साल की तुलना में सत्तर साल की उम्र में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें।

प्रधानमंत्री ने बताया कि योग लचीलापन बढ़ाने, ऊर्जा स्तर बनाए रखने, तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है और साथ ही जीवन शैली संबंधित विकारों को रोकने में भी सहयोग करता है।

श्री मोदी ने कहा, "योग का नियमित अभ्यास व्यक्ति को अपने शरीर और मन के बारे में आजीवन सीखते रहने वाला बना देता है।" उन्होंने कहा कि हम अपने बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, उतना ही बेहतर ढंग से हम स्वयं को संभाल सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी उम्र के लोगों के लिए प्रासंगिक है, जिससे योग स्वास्थ्य, कल्याण और व्यक्तिगत विकास की दिशा में जीवन भर का साथी बन जाता है।

मुख्य बिंदु

- **जब योग जीवन का तरीका बनता है, तो यह मानव एकता का आधार बन जाता है**
- **योग हमें अपने शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है; यह हमारी ऊर्जा स्तर को ऊंचा बनाए रखता है**
- **योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य तक का रास्ता दिखाता है**

योग हमें संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है

श्री मोदी ने कहा, "गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है—

युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु।
युक्त स्वप्न अव-बोधस्य, योगो भवति दुःखहा॥

अर्थात्, संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से, योग दुःखों का नाश करने वाला हो जाता है।"

उन्होंने कहा कि संतुलन ही योग की नींव है और एक संतुष्ट जीवन के लिए यह उतना ही जरूरी है। योग संतुलित तरीके से जीने की कला सिखाता है। यह लोगों को मार्गदर्शन देता है कि क्या किया जाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, जिससे उन्हें एक स्वस्थ जीवनशैली विकसित करने में मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य तक जाने का एक मार्ग प्रदान करता है। 'युक्त चेष्टस्य कर्मसु' अभिव्यक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग लोगों में सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ विकसित करने में मदद करता है। श्री मोदी ने कहा, "ऐसी चेतना आंतरिक शांति का स्रोत बनती है और साथ ही वैश्विक सद्भाव के लिए मार्ग बनाती है। योग अब केवल व्यक्तिगत जीवनशैली अभ्यास के रूप में प्रासंगिक नहीं रहा; यह दुनिया के लिए बेहतर भविष्य बनाने की आवश्यकता बन गया है।"

श्री मोदी ने कहा कि हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लाखों लोग योग गतिविधियों में भाग लेते हैं, यह दिन यह भी अवसर प्रदान करता है कि हम योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि योग केवल एक दिन या एक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि यह उनके जीवन, उनके परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए।

योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता

प्रधानमंत्री ने इस साल 'योग 365' पहल के तहत हुई प्रगति का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा, "इस पहल के तहत 100-दिन का ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें लोगों ने अभूतपूर्व भागीदारी दिखाई। 130 देशों के 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और लोकप्रियता को दर्शाता है।" अपने संबोधन का समापन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वासी राष्ट्र की आधारशिला रखता है। सभी की भलाई की कामना करते हुए उन्होंने प्राचीन प्रार्थना का आह्वान किया, "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः" (सभी सुखी हों, सभी रोग-मुक्त हों)। ■

भारतीय संस्कृति और योग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक अलग पहचान दिलाई है: नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 21 जून, 2026 को पंजाब के फगवाड़ा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं को योग अपनाने, स्वस्थ जीवन जीने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है तथा आज 190 देश योग के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब और देश को नशामुक्त बनाने का संकल्प दोहराया तथा युवाओं से ड्रग्स के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, विरासत, तिरंगे और राष्ट्र गौरव के प्रति समर्पण बनाए रखने तथा संघर्ष, धैर्य और परिश्रम के बल पर भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा पंजाब प्रदेशाध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों और राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

श्री नितिन नवीन ने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति और योग को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने पूरे विश्व पटल पर न केवल भारतीय संस्कृति, बल्कि भारतीय परचम को भी लहराने का कार्य किया है। आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में 190 देश भारत के साथ मिलकर योग के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन और दिनचर्या में योग को आत्मसात् करें तथा स्वयं को स्वस्थ रखें। यदि इस देश का एक-एक नागरिक स्वस्थ रहेगा, तभी यह देश भी स्वस्थ होकर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

उन्होंने कहा कि मैं आज अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि हमें स्वस्थ रहना है और अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। हमें निश्चित रूप से नशे को 'ना' कहना है। नशा कहीं न कहीं हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है और यह अभिशाप घर-घर तक पहुंच रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर युवा साथियों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वे नशे को पूरे पंजाब और पूरे देश से बाहर भगाएंगे। जो हमारी जड़ों को खोखला करता है और हमारे शरीर को कमजोर करता है, उसे अपने जीवन और समाज में स्थान नहीं देना चाहिए। आज जिस प्रकार ड्रग्स का जाल कहीं न कहीं हमारे युवा साथियों के जीवन में प्रवेश कर रहा है, वह चिंता का विषय है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी के बीच इसी संकल्प और विश्वास को लेकर आए हैं कि पंजाब की धरती से ड्रग्स को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा तथा एक ऊर्जावान और शक्तिशाली भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।

मुख्य बिंदु

- **भाजपा का संकल्प है कि पंजाब की धरती से ड्रग्स को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा**
- **देश के युवाओं को अपने जीवन से ड्रग्स को पूरी तरह बाहर निकालना होगा और समाज को भी नशामुक्त बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी**
- **आज 190 देश भारत के साथ मिलकर योग दिवस मना रहे हैं**
- **'विकसित भारत' का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का साझा संकल्प है।**
- **ड्रग्स पंजाब और देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो हमारी जड़ों को खोखला करे और युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करे, उसे समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए**

श्री नवीन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम अपने युवा साथियों से पुनः उनके भविष्य, पंजाब के भविष्य और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए आग्रह करना चाहते हैं। आज हम सभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और साथ ही इस संकल्प के साथ भी जुड़ रहे हैं कि हम पंजाब तथा भारत की धरती को ड्रग्स-मुक्त बनाएंगे, ताकि हमारे युवा साथी अपना भविष्य और भारत का भविष्य सुनहरा बना सकें। श्री नवीन ने सभी से आह्वान किया कि वे मिलकर विकसित भारत का सपना देखें और उसे साकार करने की दिशा में कार्य करें। उस सपने में भारत का तिरंगा निश्चित रूप से शान के साथ लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। ■

रक्षा मंत्री ने शिलांग में किया योगाभ्यास

योग केवल स्वस्थ शरीर का आधार नहीं है, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन जीने का मार्ग है: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 जून को मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के लगभग 1,000 सैनिकों के साथ विभिन्न आसन और श्वास अभ्यास करके 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर रक्षा बलों और रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व भी किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनरैड के. संगमा, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पूर्वी वायु कमान के वायु अधिकारी कमान-इन-चीफ एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया और मुख्यालय 101 क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वधवा ने भी रक्षा मंत्री के साथ योग किया। इस अवसर पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने योग को एक समग्र विज्ञान और जीवन जीने की कला बताया, जो व्यक्ति को उसके अंतर्मन, समाज, प्रकृति और अंततः ईश्वर से जोड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि योग आंतरिक स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक लचीलेपन का मार्ग प्रशस्त करता है।

'एक्स' पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग केवल स्वस्थ शरीर का आधार नहीं है, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन जीने का मार्ग है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सतत प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत की यह सांस्कृतिक विरासत आज एक वैश्विक जन-आंदोलन बन चुकी है। योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की उस शक्ति का प्रतीक है, जो सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आइए, इस योग दिवस पर हम सभी स्वस्थ शरीर, शांत मन और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लें।" ■

केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए

योग मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार है: अमित शाह

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 जून, 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में योग सत्र में भाग लिया। यह कार्यक्रम 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस वर्ष का आयोजन 'हेल्दी एजिंग फॉर योग' (स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग) विषय पर केंद्रित था, जिसमें सभी उम्र में स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवन जीने में योग की भूमिका पर जोर दिया गया है।

यह विषय लोगों को स्वस्थ उम्र बढ़ने और समग्र कल्याण को प्राप्त करने के साधन के रूप में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, "समस्त देशवासियों को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं। योगाभ्यास से निरोगी काया, शांत मन और धैर्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। यह व्यायाम के साथ-साथ जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का मार्ग भी है। मोदी जी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व में एक जीवनशैली के रूप में अपनाया जा रहा है। आइए, संकल्प लें कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, सशक्त और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हों।"

गृह मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और इसे दुनिया भर में जीवन शैली के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है। श्री शाह ने नागरिकों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ, सशक्त और संतुलित जीवन की ओर बढ़ने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत ने जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नेतृत्व, मजबूत विदेश नीति, पारदर्शी शासन, तीव्र आर्थिक विकास और जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकारी भारत के निर्माण का आधार बना है। कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि 2020 में जब मैं देश के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, तब कोरोना का वैश्विक संकट आया। उस वक्त मोदीजी ने सामूहिक नेतृत्व का परिचय देते हुए न केवल केंद्र सरकार और उसके सभी विभागों को, बल्कि सभी राज्य सरकारों तथा 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर इतने बड़े संकट से देश को बाहर निकालने का कार्य किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन देशों में शामिल हुआ, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन विकसित की। भारत की कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में देखा जाने लगा। आज विश्व भर से लोग भारत द्वारा कोरोना संकट के प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। चाहे डोकलाम की घटना हो, रूस-यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका-ईरान के बीच तत्कालीन तनाव, विश्व को झकझोर देने वाली इन सभी घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्थिर भाव से भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को केवल एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में नहीं रहने दिया, बल्कि उसे देश की चिंता करने वाले राजनेताओं और संवेदनशील राजनीतिक दलों के एक समूह के रूप में विकसित किया। आज एनडीए 22 सरकारों, 292 लोकसभा सांसदों, 144 राज्यसभा सांसदों, 2315 विधायकों तथा 222 से अधिक विधान परिषद् सदस्यों के साथ देश के लगभग 80 प्रतिशत भूभाग और 76 प्रतिशत आबादी पर शासन कर रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के यशस्वी कार्यकाल का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संवेदनशील नेतृत्व में मात्र 12 वर्षों के भीतर 25 करोड़ लोगों तक घरों में बिजली, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गईं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बैंक खाते खोले गए, प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, 3 करोड़ लोगों तक पहली बार बिजली पहुंचाने का कार्य भी किया गया। आज 3 करोड़ लखपति दीदी इस संवेदनशीलता का अनुभव कर रही हैं। हमने स्वयं अनेक चुनाव अभियानों के दौरान गरीबों को यह कहते हुए सुना है कि भारत में गरीबों के प्रति इतनी संवेदनशीलता रखने वाला प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं आया।

उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है। देश के सामने अनेक ऐसी समस्याएं थीं, जिन्हें

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया एनडीए सरकार के 12 वर्ष पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 09 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल' को प्रदर्शित करने वाली' विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह, श्री दुष्यंत गौतम और श्री तरुण चुघ, भाजपा दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा तथा लोकसभा सांसद डॉ. संजय जायसवाल भी उपस्थित रहे।

श्री नवीन ने विशेष प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयामों का अवलोकन

इस विशेष प्रदर्शनी में गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के लिए नए अवसर, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल परिवर्तन तथा 'विकसित भारत' के संकल्प से जुड़े प्रमुख कार्यों को दर्शाया गया है

किया। इस विशेष प्रदर्शनी में गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के लिए नए अवसर, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल परिवर्तन तथा 'विकसित भारत' के संकल्प से जुड़े प्रमुख कार्यों को दर्शाया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। अंत्योदय की भावना को केंद्र में रखकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल की गई हैं। आज भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक इस परिवर्तनकारी यात्रा का सहभागी बन रहा है। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर झंडेवालान देवी मंदिर में पूजा-अर्चना

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 10 जून, 2026 को नई दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान देवी मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती की विधिवत पूजा-अर्चना की। श्री नवीन ने इस पावन अवसर पर मां के चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज तथा राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख श्री संजय मयूख भी उपस्थित रहे।

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदीजी ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनमें गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है

श्री नितिन नवीन ने कहा कि एक गरीब परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा गरीबों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनमें गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जीवन, उनका संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रसेवा का भाव हम सभी के लिए प्रेरणा और अनुकरणीय उदाहरण है। प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ■

उन्होंने सहजता से और व्यापक सहमति के साथ समाप्त करने का कार्य किया तथा अनेक मामलों में लोगों को इसका आभास भी नहीं हुआ कि इतने बड़े परिवर्तन कितनी सरलता से संभव हो गए। धारा 370 और 35ए को हटाना, तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करना, वर्षों से शरणार्थी के रूप में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता की पहचान प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करना तथा 160 वर्ष पुराने अंग्रेजों के कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू करना, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं। नक्सलमुक्त भारत का संकल्प अपने आप में ऐसा लक्ष्य था, जिसे सुनकर अनेक लोगों को आश्चर्य होता था कि यह कैसे संभव होगा। लेकिन देखते ही देखते दशकों पुरानी नक्सलवाद की समस्या काफी हद तक समाप्ति की ओर बढ़ी और वह पूरा क्षेत्र आज विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने न केवल भारत की सुरक्षा नीति को नई दिशा दी, बल्कि अनेक देशों की रक्षा नीति को भी नया दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य किया है। इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय का गठन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन से जुड़े विभागों को सशक्त बनाने की पहल, किसानों को 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा कृषि और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ विकास ने मोदीजी को किसानों का प्रिय नेता बनाया है।

श्री शाह ने कहा कि भारत, जो कभी 'फ्रेजाइल फाइव' का हिस्सा माना जाता था, आज विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम मोदीजी की दूरदर्शी सोच के उदाहरण हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को सम्मान और नीति निर्माण में उचित स्थान देने का कार्य किया गया है। हमें विश्वास है कि एनडीए द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का जो संकल्प लिया गया है, वह भी मोदीजी के नेतृत्व में पूर्ण होगा।

उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास के क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय, पीएम जनमन, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम तथा बस्तर क्षेत्र के विकास जैसे अनेक ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आज रामलला भव्य और गगनचुंबी मंदिर में विराजमान हैं, जो करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए गौरव का विषय है। मोदीजी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदार धाम का पुनर्निर्माण एवं पुनर्विकास किया गया। जिन लोगों ने संसद को सेंगोल विहीन किया था, उनकी उपस्थिति में संसद भवन में पवित्र सेंगोल की पुनः स्थापना कर यह संदेश दिया गया कि यह देश अपनी भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गगनयान मिशन, मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में बढ़ते कदम तथा स्पेस स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी ने यह सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।

श्री शाह ने कहा स्टार्टअप, पीएम गति शक्ति योजना की कल्पना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के लिए पीएलआई योजना, सागरमाला और अंतरदेशीय जलमार्ग जैसी पहलों ने देश को आने वाले तीन दशकों के लिए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की स्थापना, वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से सेना के जवानों का कल्याण तथा वैक्सीन मित्र नीति के माध्यम से वैश्विक संकट के समय भारत की एक विश्वसनीय मित्र की छवि को दुनिया भर में स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। इसी का परिणाम है कि 32 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही, 38 देशों ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर हमारे व्यापार के नए मार्ग खोले हैं और भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अथक प्रयासों से 25 वर्षों तक बिना एक भी दिन का अवकाश लिए लगातार 18 से 20 घंटे कार्य किया है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगने दिया और अपने परिवार तक सीमित रहने के बजाय पूरे देश को अपना परिवार माना। मोदीजी के नेतृत्व, उनके कार्यकाल और उनकी उपलब्धियों की सभी लोग हृदय से प्रशंसा और अनुमोदन करते हैं तथा उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। श्री शाह ने पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सभी की यही कामना है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें और उनके नेतृत्व में 'विकसित भारत', आत्मनिर्भर भारत तथा गौरवशाली भारत की संकल्पना को साकार किया जाए। ■

मुख्य बिंदु

- **मोदीजी का स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व भारतीय इतिहास का स्वर्णिम कालखंड है**
- **दशकों पुरानी नक्सलवाद, आतंकवाद और धारा 370 आदि की समस्या को 12 वर्षों में समाप्त किया**
- **मोदीजी का एक साधारण परिवार से निकलकर 25 वर्षों तक लगातार जनता का विश्वास प्राप्त करना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का प्रमाण है**

प्रेस वार्ता (शिमला)

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 13 जून, 2026 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में आर्थिक, बुनियादी ढांचे और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। श्री नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा लगातार भाजपा को मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की सहायता, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के बावजूद राज्य सरकार उसका प्रभावी उपयोग नहीं कर सकी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई योजनाओं की राशि खर्च नहीं हुई और उपयोगिता प्रमाणपत्र भी लंबित हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य सरकार को दिशाहीन, निर्णयहीन और कुप्रबंधन से ग्रस्त बताया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री राजीव बिंदल और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदीजी ने 4,398 दिनों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है और वह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बार-बार चुनावों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों की चारों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर 100 प्रतिशत परिणाम दिया है। हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को एकतरफा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सभी नगर निकाय चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाई है। इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो एक बात अवश्य कहना आवश्यक है। यहां एक धारणा बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ रही है कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है। भारत सरकार का मंत्री होने के नाते और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का मंत्री होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमेशा बढ़-चढ़कर हिमाचल को समर्थन दिया है और आर्थिक सहायता प्रदान की है। जो ड्यू नहीं है, उसे भी देने का प्रयास हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के पास फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लिए तो कदापि नहीं है। वैसे किसी के लिए भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लिए एक विशेष स्थान रखता है। हम इस संबंध में कुछ आंकड़े भी सामने रखना चाहते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को 2,381 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। वर्ष 2024-25 में ही एनडीआरएफ से पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी और रीकंस्ट्रक्शन के लिए 2,006 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के तहत रीकंस्ट्रक्शन के लिए 2,150 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और राज्य में डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट तथा डिसीजनलेस गवर्नमेंट की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार में किसी प्रकार की स्पष्ट दृष्टि या विज़न दिखाई नहीं देता। इस सरकार को लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ जाना है और पंचायती राज चुनावों के परिणाम इस दिशा का संकेत दे चुके हैं। ■

मुख्य बिंदु

- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4,398 दिनों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है और वह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं**
- **मोदी सरकार ने हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये की मदद दी, लेकिन कांग्रेस सरकार धनराशि खर्च तक नहीं कर पाई। योजनाओं का पैसा लैप्स हो रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं**
- **हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है**

भारतीय जनसंघ ही क्यों?

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

भारतीय जनसंघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन (कानपुर, 29 दिसंबर, 1952) में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा दिए गए भाषण का प्रथम भाग

भारतीय जनसंघ के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी वर्ष के लिए सर्वसम्मति से अपना प्रधान चुनकर आपने मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ का उदय केवल गतवर्ष के अक्टूबर मास की घटना है। उस समय देश के विभिन्न भागों से प्रतिनिधिगण दिल्ली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं तथा राष्ट्र की एकता व उत्थान में आने वाली बाधाओं पर विचार किया गया था। अपने जन्म के दो मास के ही अन्दर इस दल ने वयस्क मताधिकार पर आधारित साधारण चुनावों में भाग लेना निश्चित किया। साधनों के अभाव तथा तैयारी की कमी को देखते हुए यह एक साहस का कार्य था। इसका परिणाम असंदिग्ध रूप से निराशाजनक रहा। कांग्रेस ही उस समय सर्वाधिक संगठित राजनीतिक दल था और राज्यसत्ता भी उसी के हाथ में थी। ऐसी दशा में प्रतियोगी दलों की अधिकता तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों की बहुतायत के कारण उसे ही सफलता प्राप्त हुई, यद्यपि अनेक स्थानों पर बहुमत का निर्णय उसके विरुद्ध रहा। देश के अनेक स्थानों में सत्तारूढ़ दल पर चुनावों में, विशेषकर मतदान और परिणामों की घोषणा के बीच, अनीति और अनियमितता के भारी आक्षेप किए गए। इससे निर्वाचन नियम और विधियों में संशोधन की महती आवश्यकता प्रकट होती है। इतने पर भी हम जनसंघ का संदेश कितने ही प्रदेशों के कोने-कोने तक पहुंचाने में सफल हुए और सर्वसाधारण जनता का जो समर्थन हमें प्राप्त हुआ यह पर्याप्त उत्साहवर्धक था। यद्यपि अधिकांश स्थानों पर चुनाव

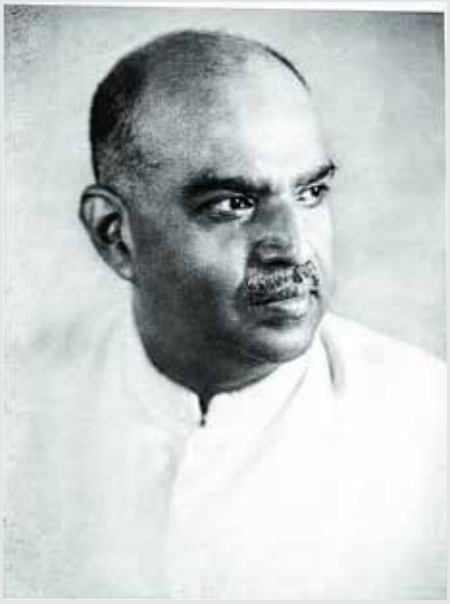

का परिणाम हमारे प्रतिकूल गया, तो भी संसद और विधान सभाओं के लिए हमारे उम्मीदवारों को लगभग 70 लाख मत प्राप्त हुए। देश के विभिन्न भागों में यात्रा करते हुए मुझे सर्वसाधारण के मन पर यह अंकित करने का अवसर प्राप्त हुआ कि जनसंघ का जन्म केवल चुनाव लड़ने मात्र के लिए नहीं हुआ है, अपितु इसका उद्देश्य एक विशाल आधार पर अपना स्थायी संगठन करने का है जिससे यह भारत की भावी उन्नति में सक्रिय हाथ बंटा सके। चुनावों के परिणाम से उत्पन्न स्वाभाविक निराशा के वातावरण का परिमार्जन करने के लिए हमें विशेष उद्योग करने पड़े। यह प्रयत्न सफल हुए हैं यह इसी बात से स्पष्ट है कि हमारे प्रथम वार्षिक अधिवेशन में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि एकत्र हैं। मुझे यह आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि हम अपनी शक्ति तथा साधनों को संगठित कर सकेंगे और हमारा यह दल शीघ्र ही जनता के हृदय में अपना स्थान बना लेगा।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण

जनसंघ की विचारधारा तथा कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण इसके जन्म के पश्चात् शीघ्र ही हो गया था। इनमें हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय, सभी मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया था। हमारे विचारधारा तथा कार्यक्रम पर होने वाली आलोचना तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए समय-समय पर हमने इनमें परिवर्तन भी किया है। जाति, मत अथवा संप्रदाय, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हमारा यह दल सभी के लिए खुला है। स्वतंत्र भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता को जाति, संप्रदाय अथवा मतादि के आधार पर खड़ा करना एक घातक भूल होगी। बिना किसी भी भेदभाव के भारतीय नागरिक के अधिकारों की समानता भारत के संविधान का आधार है जो कि प्रत्येक जनतंत्रवादी देश के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान द्वारा अपने संविधान को, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सन्निहित हैं, इस्लामी कानून तथा साम्प्रदायिक भेदभाव के आधार पर बनाने का प्रस्ताव उसकी प्रतिगामी प्रवृत्तियों को नग्न रूप में प्रस्तुत करता है।

अनेक शताब्दियों से भारत विभिन्न मत-मतान्तरों को मानने वाले लोगों की मातृभूमि रहा है। उनके व्यक्तिगत आचारधर्म की, विशेषकर उपासना और आधारभूत सामाजिक कर्तव्यों संबंधी, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता निर्विवाद है। नागरिक अधिकार तथा कर्तव्यों में सब समान हैं। स्वस्थ और प्रगतिशील सहयोग का भाव उत्पन्न करते हुए हम समाज के सभी वर्गों को

साथ लेकर चलें। यह पारस्परिक सहिष्णुता, सद्भाव और अवसर की सच्ची समानता से ही संभव होगा। हमारे दल का द्वार बिना किसी प्रकार के जाति अथवा मत संबंधी भेदभाव के उन सभी के लिए खुला है जो हमारे कार्यक्रम तथा विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यदि कुछ वर्ग हमारे साथ आना नहीं चाहते तो भी हम सर्वसाधारण जनता की सद्भावना तथा सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यह भी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए उसने बनावटी हिन्दू-मुस्लिम एकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। फलस्वरूप मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को राष्ट्र के हित में घातक समझौते पर समझौते स्वीकार करने पड़े। अन्त में जिन विघटनकारी वृत्तियों को कांग्रेस ने तुष्टीकरण के द्वारा जीतना चाहा था, उन्होंने कल्पनातीत भयंकर रूप धारण किया और उसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। उपासना पद्धति को राष्ट्रीयता का आधार बनाने, या मतपरिवर्तित व्यक्तियों अथवा उनके वंशजों द्वारा मजहब के आधार पर देश का सफलतापूर्वक विभाजन कराने की घटना और कहीं नहीं सुनी। जनसंघ का मत है कि विभाजन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, न भारत में, न पाकिस्तान में। इससे देश प्रत्येक प्रकार से दुर्बल हुआ है। यही नहीं, जिस समस्या को हल करने के लिए विभाजन स्वीकार किया गया था वही और अधिक भयंकर हो गई है और एक शान्तिपूर्ण हल निकल नहीं पा रहा है। अतः हमारे सामने अखंड भारत कोई अवास्तविक स्वप्न अथवा नारा मात्र नहीं है। यह हमारी श्रद्धा का विषय है और वह लक्ष्य है जो जनता के सहयोग और समझ से प्राप्त होगा ही।

सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था

हमारा यह विश्वास है कि भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की सर्वोच्च परम्परा के अनुरूप जनता के चारित्रिक तथा मानसिक विकास एवं भारत की पूर्ण आर्थिक उन्नति, इन दोनों के समन्वय पर ही देश की भावी उन्नति आधारित है। आर्थिक स्वातन्त्र्य के बिना जो राजनीतिक स्वातन्त्र्य हमने प्राप्त किया है वह निरर्थक होगा। यह एक अत्यन्त दुःखदायी स्थिति है कि भारत जैसा विशाल देश अपने प्रायः असीम प्राकृतिक साधनों तथा कच्चे माल के होते हुए दारिद्र्य, रोग, अविद्या तथा पतन के गर्त में पड़ा रहे। हमारे दल का यह विश्वास है कि देश को हिंसात्मक अशान्ति तथा विग्रह में बिना झोंके हुए भी हमारे लिए यह सम्भव है कि जनता के आर्थिक शोषण और मूक वेदनाओं का अन्त कर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकें। अतः भूमि और कृषि, छोटे-बड़े और बीच के उद्योगों का संगठित विकास, तथा उत्पादन वृद्धि और उचित वितरण, आदि विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में जनसंघ का दृष्टिकोण यथार्थवादी और प्रगतिशील है। अवसर की सच्ची समानता तब तक सम्भव नहीं जब तक कि जनता के निर्धन तथा पिछड़े हुए वर्गों को उचित शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधायें प्राप्त न हों, ताकि उनकी वे भारी कमियां दूर हो सकें जिनसे वे आज त्रस्त हैं।

आध्यात्मिक पुनर्जागरण

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल आर्थिक विकास न तो मनुष्य के अन्तःकरण को पूर्ण शान्ति दे सकता है और न उसके दृष्टि की पूर्ण प्राप्ति में सहायक होता है। भारत ने उन मनः प्रवृत्तियों को जन्म दिया है जो उन्नति और प्रगति का दावा करने वाले अनेक देशों से भिन्न उसकी अपनी विशेषता है। जीवन में सादगी, सेवा और त्याग का भाव, संतोष तथा निःस्वार्थ, निःस्पृहता का दृष्टिकोण, बन्धुत्व एवं पावित्र्य का भाव, शक्ति और विनम्रता, सहिष्णुता तथा ऐक्य का योग अनादि काल से सुसंस्कृत मानवीय आचार का आदर्श रहा है। हमारा देश अच्छाई तथा बुराई का एक विचित्र सम्मिश्रण है। मानव जीवन के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करने वाले सत्य को यहां अति सरल ढंग से उदार हृदय होकर प्रकट किया गया है। इन सत्यों को आचरण में प्रकट करने वाले इक्के-दुक्के उदाहरण अवश्य मिलते हैं, किन्तु इन महान् शिक्षाओं के साथ अधिकांश लोगों के आचरण की संगति कठिनाई अवश्य पहुंचाएगा। प्रश्न केवल यह है कि यदि हम इसी गति से चलते रहे और दशा को अधिकाधिक बिगड़ने दिया तो क्या पीड़ित जनता का धैर्य अटूट बना रहेगा और क्या वे सदा ही इसी प्रकार चुपचाप सहन करते रहेंगे? यदि सरकार द्वारा अपने कर्तव्यपालन में असफल होने पर जनक्षोभ उसके विरोध में एक बार भी भड़क उठा तो हमें बहुत अधिक धन-जन की हानि उठानी पड़ेगी, जो शायद अन्यथा बचाई जा सकती है।

इस योजना के इसी रूप में भी पूर्ण होने के सम्बन्ध में कुछ चेतावनी के शब्द कह देना आवश्यक है। इसको क्रियान्वित करने के लिए बनाई गयी व्यवस्था पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिए ऐसे ही लोगों का चुनाव हो जो पूर्ण योग्य हों और जिनमें हृदय की विशालता तथा सेवा का भाव हो। इन गुणों के कारण वे केवल वेतन प्राप्त कर्मचारी न होकर योजनाबद्ध राष्ट्रीय विकास के नवीन युग को लाने वाले निमित्त होंगे। अतः उनका चुनाव पक्षपात, संरक्षकता अथवा दलगत भावनाओं के अनुसार कदापि नहीं होना चाहिए। किसी भी संगठित योजना की सफलता के लिए सार्वजनीन सहयोग का सच्चा वातावरण आवश्यक है। इतने गाने-बाजे से स्थापित किए गये 'भारत सेवक समाज' की प्रगति भी एक दल-निरपेक्ष संगठन के रूप में नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त आज के सत्ताधारियों द्वारा योजना का दुरुपयोग अपने दलीय स्वार्थों के लिए किए जाने की भी बहुत गुंजाइश तथा संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो इससे न केवल नितान्त आवश्यक सार्वजनीन सहयोग तथा उत्साह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, वरन् इस योजना को चलाने की सारी व्यवस्था ही दूषित हो जाएगी और इस प्रकार इसकी सफलता के सभी अवसर नष्ट हो जायेंगे। योजना के अनुसार राज्य के द्वारा उठाये गये किसी भी निर्णय, कार्य के ऊपर आदि से अन्त तक कठोर देखरेख रखना आवश्यक होगा। राज्य के द्वारा उठाये गये कुछ कार्यों में अच्छी सफलता मिली है, उदाहरणार्थ सिन्दरी का खाद का कारखाना, चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी, दामोदर घाटी कारपोरेशन आदि। इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि सामान की बरबादी और अन्य अनियमितता तथा भूलें जो पहले हो चुकी हैं, फिर भविष्य में भी दोहराई जायें।

क्रमशः

लेख

‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ से ‘भारतीयता में विश्वास’ तक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दौर की एक खास बात यह भी है कि इसमें भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों, मूल्यों और परंपराओं को लेकर गर्व की भावना बहुत मजबूत रही है

राम नाथ कोविंद
भारत के पूर्व राष्ट्रपति

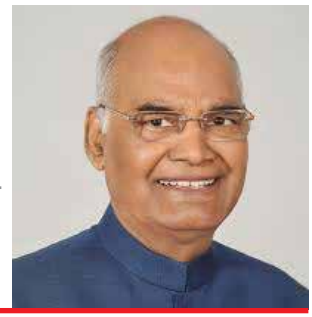

10 जून, 2026 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक विशेष अवसर है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह कार्यकाल भारत के लिए भी एक निर्णायक दौर है, जो किसी अन्य रिकॉर्ड से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है।

26 मई, 2014 से देश की राजनीति ने ‘भारतीयता’ की ओर एक निर्णायक मोड़ लिया, जिसकी वकालत महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबासाहेब बी.आर. अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और आधुनिक भारत के कई अन्य निर्माताओं ने की थी। इन लोगों ने अपनी विरासत एवं परंपराओं पर गर्व करने की बात कही थी, साथ ही हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नये दृष्टिकोण से देखने की कल्पना की थी।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समावेशिता के साथ ‘राजाजी’ मॉडल को आगे बढ़ाया है। जैसाकि हम जानते हैं कि राजाजी नेहरूवादी अर्थव्यवस्था के ‘कमांड एंड कंट्रोल’ मॉडल के कड़े आलोचक थे, जिसके कारण ‘कोटा, परमिट और लाइसेंस राज’ का उदय हुआ था।

25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉ. अंबेडकर के ऐतिहासिक और विद्वतापूर्ण बयान के बावजूद— जिसमें उन्होंने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र के तत्व 2,500 साल पुरानी बौद्ध संस्थाओं में मिलते थे और उन बौद्ध संस्थाओं ने उस समय की प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं से लोकतांत्रिक तौर-तरीके अपनाए होंगे— राजनीतिक चर्चाओं में हमारे छात्रों और कानूनविदों को यह विश्वास दिलाया गया कि हमारा लोकतंत्र पश्चिमी देशों की देन है।

श्री मोदी वैश्विक मंचों पर यह कहते रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है और वे प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और तौर-तरीकों का जिक्र करते हैं। दुनिया अब इस बात को समझ रही है कि भारत न केवल सबसे प्राचीन, बल्कि सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र भी है।

भारत के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं की संख्या दुनिया के बाकी किसी भी हिस्से के लिए हैरान करने वाली बात है। दिलचस्प बात यह है कि मतदाताओं की यह संख्या स्वतंत्रता के समय भारत की कुल आबादी से लगभग तीन गुना अधिक है। मतदाताओं की संख्या के साथ-साथ चुनावी समीकरण भी और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। 1951-52 के आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक पार्टियां थीं, जबकि 2024 के आम चुनाव में 744 पार्टियों ने हिस्सा लिया।

नेहरू के समय की तुलना में लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं अधिक बढ़ गयी हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और लोगों के साथ भरोसे का संबंध बनाए रखना श्री मोदी की एक बड़ी कामयाबी है; उनकी लोकप्रियता रेटिंग नेहरू की तुलना में लगातार ऊंची बनी हुई है, जबकि नेहरू को अपने कार्यकाल के दौरान अपनी साख और लोकप्रियता में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था।

1950 और 1960 के दशक या फिर 1970 के दशक में भी दुनिया भर में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए कई नेताओं का कार्यकाल काफी लंबा रहा। 21वीं सदी में राजनीतिक नेताओं का कार्यकाल बहुत कम हो गया है। श्री मोदी इस वैश्विक चलन में अपवाद हैं।

यह सही कहा गया है कि कोई भी समाज तब तक सुदृढ़ और गौरवान्वित नहीं हो सकता जब तक उसमें आत्म-सम्मान की भावना न हो। सदियों से भारत सभ्यता और संस्कृति की उत्कृष्टता का एक शानदार

भारत के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं की संख्या दुनिया के बाकी किसी भी हिस्से के लिए हैरान करने वाली बात है। दिलचस्प बात यह है कि मतदाताओं की यह संख्या स्वतंत्रता के समय भारत की कुल आबादी से लगभग तीन गुना अधिक है। मतदाताओं की संख्या के साथ-साथ चुनावी समीकरण भी और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। 1951-52 के आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक पार्टियां थीं, जबकि 2024 के आम चुनाव में 744 पार्टियों ने हिस्सा लिया

उदाहरण रहा है। हालांकि, औपनिवेशिक शासकों द्वारा पैदा की गई हीन भावना स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही। स्वतंत्रता के बाद भी कई औपनिवेशिक प्रथाएं जारी रहीं और यहां तक कि उन्हें बढ़ावा भी दिया गया; साथ ही, एक ऐसा कुलीन अल्पसंख्यक वर्ग बन गया जिसने थॉमस बैबिंगटन मैकाले के विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाया।

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में अंग्रेजी को सत्ता की भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया। नेहरू के दौर और उसके ठीक बाद के समय में कुलीन वर्ग के बीच भारतीय वस्तुओं को लेकर शर्मिंदगी का भाव देखा गया। जो लोग भारतीय भाषाओं में बात करते, काम करते या अपनी बात रखते थे, उन्हें कमतर या हीन समझा जाता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और प्रतीकों की उपेक्षा करके विदेशी धरती पर पनपी विचारधाराओं और प्रथाओं को प्राथमिकता दी गई। भारतीय परंपराओं के स्वाभाविक निरंतर विकास और विस्तार की कमी के कारण आत्मविश्वास और नई सोच की कमी पैदा हुई।

श्री मोदी ने भारतीय भाषाओं, प्रणालियों, प्रतीकों और मान्यताओं को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अब, लोगों में भारतीय होने और भारतीयता को जाहिर करने को लेकर गर्व की भावना दिखती है। मेरी कई देशों की यात्राओं के दौरान विदेशों में रहने वाले भारतीयों (डायस्पोरा) ने मेरे साथ गर्व की इसी नई भावना को साझा किया।

श्री मोदी ने मानसिक रूप से इस औपनिवेशिक सोच से आजाद होने के लिए अंग्रेजी भाषा के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम को चुना। नवंबर, 2025 में हुए उस कार्यक्रम में उन्होंने भारत के लोगों से मैकाले की विरासत में रची-बसी औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने के लिए 10 साल का राष्ट्रीय संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं है; बल्कि यह एक आत्मविश्वास से भरा एक नया मॉडल है।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशक और पिछले 12 वर्षों के बीच का अंतर एक बड़े बदलाव को दिखाता है। नेहरू के दौर में सांस्कृतिक और आर्थिक मान्यताओं को लेकर पश्चिम से मंजूरी और मदद पाने की चाहत स्पष्ट दिखायी देती थी। वहीं, श्री मोदी के दौर में मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिखता है, जो दुनिया में होने वाली उथल-पुथल का भी सामना करने में सक्षम है।

श्री मोदी के दौर की एक खास बात यह भी है कि इसमें भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों, मूल्यों और परंपराओं को लेकर गर्व की भावना बहुत मजबूत रही है।

हमारे ही परिवार के एक युवा लड़के ने, जो काफी समझदार है, एक ऐसी बात कही जिससे उसकी परिपक्वता और उसकी पीढ़ी की सोच का पता चलता है। उसने मुझसे कहा कि मैं नेहरू के भारत में बड़ा हुआ, जबकि वह मोदी के भारत में बड़ा हो रहा है। उस लड़के ने यह भी बताया कि इस वजह से उसकी पीढ़ी की स्थिति बेहतर है। ■

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में अंग्रेजी को सत्ता की भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया। नेहरू के दौर और उसके ठीक बाद के समय में कुलीन वर्ग के बीच भारतीय वस्तुओं को लेकर शर्मिंदगी का भाव देखा गया। जो लोग भारतीय भाषाओं में बात करते, काम करते या अपनी बात रखते थे, उन्हें कमतर या हीन समझा जाता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और प्रतीकों की उपेक्षा करके विदेशी धरती पर पनपी विचारधाराओं और प्रथाओं को प्राथमिकता दी गई

लेख

पीएमएसएमए का एक दशक: मातृ स्वास्थ्य का कायाकल्प और सुरक्षित मातृत्व की ओर भारत के तेजी से बढ़ते कदम

जगत प्रकाश नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री

हर सुरक्षित गर्भ राष्ट्र की अपनी महिलाओं के लिए प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। हमारे देश के हर साल लगभग 2.9 करोड़ गर्भधारण होते हैं। इस बड़े पैमाने पर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए मजबूत स्वास्थ्य तंत्रों, निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, समय पर हस्तक्षेप और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच की जरूरत है।

पिछले दशक में देश में मातृत्व से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इस प्रगति का आधार मातृत्व स्वास्थ्य में निरंतर निवेश, सेवा डिलीवरी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक भागीदारी है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता रखी है कि हर महिला को उसकी समूची गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके।

इस कायाकल्प के केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) है। यह अभियान पिछले 10 वर्षों से देश भर में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दे रहा है।

पीएमएसएमए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की कल्पना है जिसे 9 जून, 2016 को शुरू किया गया था। यह सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भ की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान हर महीने के नौवें दिन मुफ्त, सुनिश्चित, समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं मुहैया कराने का राष्ट्रव्यापी अभियान है।

यहां हर माह के नौवें दिन के चयन का एक गहरा महत्व है। गर्भावस्था नौ बेशकीमती महीनों की यात्रा है। इनमें से हर माह नई उम्मीद, अनुमान और जिम्मेदारी लेकर आता है। हर महीने का नौवां दिन मातृ स्वास्थ्य को समर्पित कर पीएमएसएमए यह याद दिलाता है कि प्रत्येक गर्भावस्था स्वस्थ शिशु के सुरक्षित आगमन तक सभी नौ महीनों में निरंतर देखभाल, निगरानी और सहायता की हकदार है।

मातृ स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि कोई भी गर्भावस्था जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं होती। आज सामान्य दिखाई देने वाली गर्भावस्था में कल गंभीर जटिलताएं विकसित हो सकती हैं। पीएमएसएमए में यह स्वीकार किया गया है कि कोई भी गर्भावस्था बिना किसी चेतावनी के उच्च जोखिम वाली बन सकती है। लिहाजा, इस अभियान में जोखिमों की जल्दी पहचान कर उनकी नजदीकी निगरानी तथा समय पर निर्देशन और प्रबंधन सुनिश्चित करने का सरल लेकिन परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उच्च जोखिम वाली हर चिह्नित गर्भावस्था माता की जान बचाने तथा समयपूर्व प्रसव, शिशु में जटिलताओं या जीवनपर्यंत विकलांगता को रोकने का एक अवसर है। इस अभियान में जटिलताओं के उपचार के बजाय उनकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह इसने भारत के मातृ स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत कर करोड़ों महिलाओं के लिए गर्भावस्था को सुरक्षित बनाया है।

पीएमएसएमए की प्रमुख विशेषताओं में से एक निर्धारित दिन को संस्थागत रूप देकर विशेषज्ञ के नेतृत्व में प्रसवपूर्व सेवा सुनिश्चित करना है। इससे देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में अनुमानेयता, जवाबदेही और निरंतरता आई है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की लगभग 25 उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था स्थितियों के लिए जांच की जाती है। इनमें खून की गंभीर कमी, उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन मधुमेह, संक्रमण और अन्य ऐसी जटिलताओं की जांच शामिल है जिनके पता नहीं चलने पर माता और शिशु का जीवन जोखिम में पड़ सकता है।

चूंकि इस बात के साक्ष्य सामने आए कि गर्भधारण के ज्यादा जोखिम वाले मामलों में पीएमएसएमए के तहत किसी विशेषज्ञ/चिकित्सक द्वारा नियमित प्रसव पूर्व जांच के बाद भी निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत सरकार ने 2022 में 'विस्तारित पीएमएसएमए' (इ-पीएमएसएमए) की शुरुआत करके इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाया है।

ई-पीएमएसएमए के तहत अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को नियमित पीएमएसएमए जांच के अलावा अतिरिक्त चिकित्सीय सलाह (फ़ॉलो-अप विज़िट) की सुविधा भी मिलती हैं, ताकि सुरक्षित डिलीवरी तक समय पर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। इस पहल के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की नाम-आधारित ट्रैकिंग शुरू की गई है और प्रसव के बाद 45 दिन तक फॉलो-अप परामर्श के लिए इसे बेहतर किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कमज़ोर स्थिति वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के तुरंत बाद की कुछ अवधि के दौरान निरंतर देखभाल मिलती रहे। अतिरिक्त जांच के लिए ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के साथ जाने वाली मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा कार्यकर्ता) के लिए प्रोत्साहन राशि के प्रावधान ने रेफरल के नियमों और निरंतर देखभाल को और अधिक सुदृढ़ किया है।

कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही को और अधिक बेहतर करने के लिए, भारत सरकार ने एक केंद्रीकृत पीएमएसएमए डिजिटल पोर्टल विकसित किया है, जो देश भर में कार्यक्रम प्रबंधन के मुख्य आधार के तौर पर काम करता है।

यह पोर्टल सेवा वितरण की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की नाम-आधारित ट्रैकिंग, कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और सामुदायिक स्वयंसेवकों को भी कार्यक्रम में योगदान देने की सुविधा देता है जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'जन भागीदारी' के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलती है, यही पीएमएसएमए की मूल भावना है।

पीएमएसएमए की सफलता भारत के मातृ स्वास्थ्य तंत्र में विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय के महत्व को भी रेखांकित करती है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन), राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस), पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आयुष्मान भारत और मिडवाइफ सेवाएं, प्रसवोत्तर देखभाल का अनुकूलन (ओपीएनसी) जैसी पहलों के साथ मिलकर काम करते हुए पीएमएसएमए ने गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान भी महिलाओं के लिए निरंतर देखभाल के एक मजबूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस परिवर्तन के केंद्र में भारत के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्त्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, मिडवाइफ और चिकित्सा अधिकारी हैं। सामुदायिक भागीदारी, परामर्श (काउंसलिंग), जांच, रेफरल और फॉलो-अप परामर्श में उनके अथक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि मातृ स्वास्थ्य सेवाएं देश के सबसे दूरदराज और वंचित क्षेत्रों की महिलाओं तक भी पहुंच सकें।

इन सामूहिक प्रयासों का प्रभाव राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणामों में तेजी से दिखाई दे रहा है। वर्ष 2022-24 के नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) के अनुमानों के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) घटकर प्रति 1,00,000 जीवित शिशुओं पर 87 हो गया है। यह देश को 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख जीवित शिशुओं पर 70 से कम करने के संवहनीय विकास लक्ष्य को हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है।

ये सुधार माताओं की सेहत से जुड़े व्यापक पैमानों में भी दिखाई देते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6, 2023-24) की रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव (संस्थानों/अस्पतालों में होने वाले प्रसव) की दर एनएफएचएस-5 (2019-21) के 88.6 प्रतिशत से बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि प्रसव पूर्व देखभाल का दायरा एनएफएचएस-5 के 92.6 प्रतिशत से सुधरकर एनएफएचएस-6 में 95.9 प्रतिशत हो गया है। ये उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि पहले की तुलना में अब कहीं अधिक संख्या में महिलाएं आवश्यक मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रही हैं, जिससे जटिलताओं का जल्द पता लगाने और समय पर उचित उपचार के बहुमूल्य अवसर पैदा हो रहे हैं। दुनिया में हर साल जन्म लेने वाले सबसे बड़े समूहों में से एक का प्रबंधन करते हुए ऐसी प्रगति हासिल करना भारत के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के व्यापक पैमाने और प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

प्रभावशाली दशक

पिछले एक दशक में पीएमएसएमए का दायरा और पहुंच अभूतपूर्व रही है। 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से देश भर में इस कार्यक्रम के तहत 7.5 करोड़ से अधिक प्रसव पूर्व जांच की जा चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएमएसएमए ने 1.17 करोड़ से अधिक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के मामलों की पहचान करने में सक्षम बनाया है।

ये उपलब्धियां केवल आंकड़े नहीं हैं। ये उन लाखों माताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का समय रहते पता लगाया गया, जिनकी गर्भावस्था की बारीकी से निगरानी की गई और जिन्हें समय पर अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से उनकी और उनके नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकी।

हर मां के लिए गर्भधारण उम्मीद का एक नया सफर होती है। हर परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत का वादा है। फिर भी, दुनिया भर में बहुत सी महिलाओं के लिए गर्भावस्था में ऐसे जोखिम बने हुए हैं जिनसे बचा जा सकता है। पीएमएसएमए की शुरुआत एक सरल लेकिन इस मजबूत सोच के साथ हुई थी कि जीवन देते समय किसी भी महिला को अपना जीवन नहीं गवांना पड़े और किसी भी परिवार को गर्भावस्था से जुड़ी ऐसी जटिलता के कारण मां को नहीं खोना पड़े।

जब देश में पीएमएसएमए का एक दशक पूरा हो रहा है, तो यह केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। हम लाखों सुरक्षित गर्भधारण, स्वस्थ माताओं, नवजात शिशुओं के लिए अधिक मजबूत शुरुआत और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, समुदायों व परिवारों के उन सामूहिक प्रयासों का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने इस बड़े बदलाव में अपना योगदान दिया है।

आगे की राह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की ट्रैकिंग, मिडवाइफरी-आधारित सेवाओं, डिजिटल नवाचारों और मातृ स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत व समान पहुंच को लगातार मजबूत करना होगा। पीएमएसएमए के अनुभव ने एक सरल सत्य को फिर से साबित किया है: जब हर गर्भावस्था की निगरानी की जाती है, हर जोखिम का समय रहते पता लगा लिया जाता है और हर महिला को समय पर सम्मानजनक व गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिलती है, तो जन्म देते समय माताओं की मौत को रोका जा सकता है, न कि उसे अपरिहार्य माना जाए।

इसलिए, पीएमएसएमए के दस वर्ष पूरा होना महज किसी कार्यक्रम का जश्न मनाना नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब राजनीतिक प्रतिबद्धता, सशक्त कार्यकर्ता, डिजिटल नवाचार, जन भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एक ही मकसद 'हर मां सुरक्षित को रखने और हर नवजात शिशु को स्वस्थ रखने' के लिए साथ मिलकर काम करती हैं, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। ■

लेख

मोदी की यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एवं पारदर्शिता का प्रतीक है

नीतीश कुमार

राज्यसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री

भारत जैसे विशाल और प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में जनता का विश्वास निरंतर कायम रखना काफी कठिन कार्य है। फिर भी, लगातार राजनीतिक खींचतान और जनता की कड़ी नजर के बीच नरेन्द्र मोदी पर लोगों का विश्वास लागातार बना हुआ है। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है।

हालांकि, हम भारत के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मैं एक ही पीढ़ी के हैं, जिसकी राजनीतिक सोच इमरजेंसी के दौरान बनी थी। हमने लोकतांत्रिक आज़ादी पर हुए हमले को स्वयं देखा और उस आंदोलन का हिस्सा रहे, जिसने लोकतंत्र को बहाल करने की कोशिश की। वह संघर्ष केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हमारी समझ को आकार दिया।

दशकों तक यह धारणा रही कि सबसे ऊंचे पद कुछ खास लोगों या प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में जन्मे लोगों के लिए ही आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इस धारणा को चुनौती दी है। साधारण शुरुआत से उठकर सबसे ऊंचे चुने हुए पद तक पहुंचने वाले वे लाखों युवा भारतीयों, खासकर साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। उनकी यात्रा इस विश्वास को मजबूत करती है कि एक जीवंत लोकतंत्र में दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और काबिलियत से जन्म और हालात की बाधाओं को पार किया जा सकता है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता का एक प्रतीक है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कई अन्य महान समाजवादी नेताओं का अनुयायी होने के नाते मैंने हमेशा राजनीति को लोगों की भलाई सुनिश्चित करने का एक माध्यम माना है। लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना किसी भी राजनीतिक नेता की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड शानदार रहा है। गरीबी उन्मूलन पर उनके विशेष ध्यान के साथ एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। शौचालय, बैंक खाते, घर, गैस कनेक्शन, नल का पानी, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और कई अन्य बुनियादी सुविधाएं करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, महिलाओं, गरीब परिवारों और विकास कार्यक्रमों के पहली पीढ़ी के लाभार्थियों के बड़े वर्ग अब स्वयं को भारत की विकास गाथा में सक्रिय भागीदार के रूप में देखने लगे हैं। युवाओं को विशेष योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता के नए अवसर मिले हैं। इन समूहों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है।

मैंने यह भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के कल्याण और सम्मान पर कितना जोर दिया है। उनकी कई योजनाओं से महिलाओं को सीधे लाभ हुआ है और उनके रोजमर्रा के जीवन की मुश्किलें कम हुई हैं। बिहार में मेरा अनुभव रहा है कि जब विकास के कामों के केंद्र में महिलाएं होती हैं, तो समाज तेजी से विकास करता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बिहार में हमारे 'जीविका' प्रयोग की सफलता की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है।

कई सालों तक मुख्यमंत्री रहने के नाते मैं उन चुनौतियों को

दशकों तक यह धारणा रही कि सबसे ऊंचे पद कुछ खास लोगों या प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में जन्मे लोगों के लिए ही आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इस धारणा को चुनौती दी है। साधारण शुरुआत से उठकर सबसे ऊंचे चुने हुए पद तक पहुंचने वाले वे लाखों युवा भारतीयों, खासकर साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। उनकी यात्रा इस विश्वास को मजबूत करती है कि एक जीवंत लोकतंत्र में दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और काबिलियत से जन्म और हालात की बाधाओं को पार किया जा सकता है

जानता हूं जो यह पक्का करने में आती हैं कि लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे। केवल अच्छी नीयत पर्याप्त नहीं होती। योजनाओं को सही ढंग से लागू करना आवश्यक होता है। मैंने यह भी देखा है कि नीतिगत निर्णयों को परिणामों में बदलने के लिए लगातार निगरानी, सुधार, प्रशासनिक फोकस और हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की एक खास बात यह रही है कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि गवर्नेंस का असर नागरिकों को स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। उन्होंने हमेशा काम में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान दिया है। टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जैसे डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के बीच का अंतर बहुत हद तक कम हो गया है। जब सरकारी लाभ लोगों तक अधिक असरदार तरीके से और बिना किसी लीकेज के पहुंचते हैं, तो संस्थाओं में जनता का भरोसा मजबूत होता है। नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के लगातार जुड़ाव से यह भरोसा और भी मजबूत होता है, जिससे सरकार और लोगों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका लंबा और कामयाब कार्यकाल शामिल है। वास्तव में वे जल्द ही चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25 साल की सेवा पूरी करने वाले हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस अनुभव ने उन्हें राज्यों की आवश्यकताओं की गहरी समझ दी है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में सहकारी संघवाद के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखती है।

मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मैंने स्वयं देखा कि राजनीतिक हालात चाहे जैसे भी हों, उन्होंने हमेशा बिहार के विकास में सहयोग दिया। मैं विशेष तौर पर उस सहयोग की बात करना चाहूंगा जो बिहार को 2024–25 और 2025–26 के बजट में मिला; इसमें मखाना बोर्ड बनाना, भागलपुर में पावर प्लांट लगाना और बाढ़ प्रबंधन व कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देना शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी बिहार की अनोखी संस्कृति और परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को बिहार का मखाना, मधुबनी पेंटिंग और प्रदेश के दूसरे उत्पाद उपहार में देकर वैश्विक मंच पर बिहार की विरासत को सम्मान दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले—एक ऐसी मांग जो दशकों से अधूरी थी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की एक खास बात यह रही है कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि गवर्नेंस का असर नागरिकों को स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। उन्होंने हमेशा काम में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान दिया है। टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जैसे डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के बीच का अंतर बहुत हद तक कम हो गया है

2014 से पहले के दशक की तुलना में केंद्र से मिलने वाले सहयोग और निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है। गंगा नदी पर महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, हवाई अड्डों का विकास और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी से बिहार की विकास यात्रा ने गति पकड़ी है। खास तौर पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा बदलाव बेहद सकारात्मक है, क्योंकि यह हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रा करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे के विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण के दूसरे प्रोजेक्ट्स ने शानदार सुधार हुआ है।

मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है और उसका समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की जो खूबियां उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती हैं, उनमें से एक है भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका कड़ा रुख। ऐसे नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं जिन्होंने सत्ता के पदों पर दशकों बिताए हों और जिनकी ईमानदारी पर कभी कोई दाग न लगा हो। संस्थागत सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के साथ-साथ, उन्होंने भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर, राजनीतिक इच्छाशक्ति भी दिखाई है।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की एक विशेष बात यह रही है कि वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है। एक भारतीय के तौर पर मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मामलों में हमारी बात का सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। अलग-अलग देशों और समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा शांति और प्रगति के पक्ष में खड़े रहे हैं। परिणामस्वरूप, दुनिया 21वीं सदी में वैश्विक विकास के एक प्रमुख कारक के रूप में हमारे देश को उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहा है।

सार्वजनिक जीवन में कई दशक बिताने के बाद मैं जानता हूं कि नेतृत्व के लिए लगातार प्रयास, अथक परिश्रम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगातार यात्रा करने, लोगों के साथ नियमित रूप से जुड़ने, सरकारी कामकाज की विस्तृत समीक्षा करने और साथ ही एक बड़े दृष्टिकोण से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री मोदी की अथक ऊर्जा और समर्पण ने उन्हें इतने लंबे समय तक लोगों का भरोसा बनाए रखने में मदद की है। जब वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो यह उनके सार्वजनिक जीवन में योगदान का जश्न मनाने और उन्हें भविष्य में और भी कई उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं देने का अवसर है। मैं उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और देश की सेवा में निरंतर सफलता की कामना करता हूं। ■

लेख

भारत ने श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई के लिए खाड़ी देश में अवसरों के द्वार खोले

पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

1 जून से लागू हो रहा भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस मिशन की एक निर्णायक उपलब्धि है, जिसका लक्ष्य नए बाजार खोलने और रोजगार सृजन को गति देने के जरिये भारत के छात्रों, कारीगरों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के लिए वैश्विक समृद्धि के मार्ग बनाना है।

भारत और ओमान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें वे व्यापारी परिवार भी शामिल हैं, जिनकी जड़ें 200–300 साल पुरानी हैं। ओमान से भारत को भेजी जाने वाली वार्षिक धनराशि लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जबकि देश में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम कार्यरत हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह तुरंत ही ओमान में 98 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की सुविधा देता है, जिसमें 99.38 प्रतिशत निर्यात शामिल है।

यह सीईपीए से पहले की प्रणाली की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। पहले की प्रणाली में केवल 15.3 प्रतिशत भारतीय निर्यात ओमान में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते थे। भारत की ऐसी वस्तुएं, जिन पर वर्तमान में ओमान में 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जिनकी कीमत लगभग 3.64 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर है, अब काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए यह समझौता परिवर्तनकारी हो सकता है, क्योंकि सीईपीए से लाभान्वित होने वाले कई क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की प्रमुखता है। लोहा और इस्पात, वस्त्र, चमड़ा, वाहन कल-पुर्जे और औद्योगिक उपकरण जैसे कुछ क्षेत्रों में एमएसएमई को बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के युग में सीईपीए भारतीय निर्यातकों को, जो आर्थिक मंदी और बढ़ते व्यापार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, अपने बाजारों को विविध बनाने और परंपरागत बाजारों पर निर्भरता कम करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

रोजगार सृजन

यह व्यापार समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण और कुछ इंजीनियरिंग क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है, जो भारत के प्रमुख रोजगार प्रदाता हैं।

ओमान को होने वाले वस्त्र निर्यात में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, कोयंबटूर, करूर, भदोही, मुरादाबाद, जयपुर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख क्लस्टर में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। भारत भर के कारीगर और बुनकर भी अपने उत्पादों की उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभान्वित होंगे।

भारत भर में, विशेष रूप से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत चमड़ा और जूता के प्रमुख केंद्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

रत्न और आभूषण क्षेत्र एक अन्य उदाहरण है, जो दिखाता है कि सीईपीए रोजगार वृद्धि को किस प्रकार तेज करेगा। भारत के पास पहले से ही कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, सोने और चांदी के आभूषण तथा हस्तनिर्मित आभूषण उत्पादन में मजबूत क्षमताएं हैं। शुल्क बाधाओं के हटने से भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में ओमान को होने वाला निर्यात बढ़कर 150 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के आभूषण निर्माण केन्द्रों में महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं सृजित होने की उम्मीद है।

भारत और ओमान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें वे व्यापारी परिवार भी शामिल हैं, जिनकी जड़ें 200–300 साल पुरानी हैं। ओमान से भारत को भेजी जाने वाली वार्षिक धनराशि लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जबकि देश में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम कार्यरत हैं

किसान और मछुआरे

घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि हितों की सुरक्षा के लिए भारत ने गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, डेयरी, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, तिलहन, चाय, कॉफी और शहद जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरीफ छूट नहीं दी है।

घी, शहद, मीठे बिस्कुट, अंडे और कुछ मिष्ठान्न उत्पादों में भारत को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे देश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

यह समझौता भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रमाणन की स्वीकृति और मान्यता भी प्रदान करता है, जो भारतीय किसानों को ओमान में, जो एक प्रमुख खाद्य आयातक है, जैविक उत्पाद बेचने के लिए विशाल अवसर देगा।

समुद्री उत्पादों में भी विशाल संभावनाएं हैं, जिनका अब तक उपयोग नहीं हो पाया है। 2022 और 2024 के बीच ओमान का समुद्री उत्पादों का आयात लगभग 119 मिलियन डॉलर था। भारत से आयात केवल 7.75 मिलियन डॉलर था, जिससे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात जैसे झींगा और जमे हुए कटलफिश के लिए विशाल अवसर मौजूद हैं। श्रम-गहन समुद्री उत्पाद उद्योग मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत-श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और निर्यात संचालन में अतिरिक्त नौकरियां उत्पन्न कर सकता है।

दवा और पारंपरिक चिकित्सा

यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए और टीजीए जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित भारतीय दवाएं 90 दिनों के भीतर ओमान में स्वचालित विपणन प्राधिकार प्राप्त करेंगी — जो भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए एक बड़ी सफलता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि सीईपीए भारत की पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के लिए अवसर पैदा करता है। यह पारंपरिक चिकित्सा में संयुक्त अनुसंधान की व्यवस्था करता है।

सेवाएं और आवागमन

समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू सेवा और आवागमन में निहित है। ओमान ने भारत के लिए विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है, जिनमें पेशेवर सेवाएं, कंप्यूटर और आईटी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, अनुसंधान और विकास तथा पर्यावरण सेवाएं शामिल हैं। लेखा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, निर्माण, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को बेहतर बाज़ार पहुंच से लाभ मिलने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण रूप से ओमान ने भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के लिए आवागमन प्रतिबद्धताओं में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की है। अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों और संविदा सेवा प्रदाताओं को चार साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि व्यवसाय आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों को आसान अस्थायी प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इसने अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों के लिए ऊपरी-सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की मोदी सरकार की पहल प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा है।

ओमान के साथ समझौता याद दिलाता है कि व्यापार; विकास, रोजगार सृजन और साझा समृद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण है। एक विभाजित और संरक्षणवादी दुनिया में पीएम मोदी स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि एक नया, आत्मविश्वासी भारत पीछे नहीं हटेगा। यह साझेदारियों, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ■

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा

स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 43,746 करोड़ रुपये से लगभग चार गुना बढ़कर इस स्तर पर पहुंचा है

रक्षा मंत्रालय द्वारा 17 जून को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है और वित्त वर्ष 2020-21 के 84,643 करोड़ रुपये के आंकड़े से 110 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 43,746 करोड़ रुपये से लगभग चार गुना बढ़कर इस स्तर पर पहुंचा है।

रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल उत्पादन में लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 24 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 22 प्रतिशत से अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 42,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह रक्षा इकोसिस्टम में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उत्पादन में हुई वृद्धि ने वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों को दर्शाती है। ■

लेख

पीएम स्वनिधि योजना

पथ विक्रेताओं के सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन की परिवर्तनकारी यात्रा

मनोहर लाल खट्टर
केंद्रीय आवासन और
शहरी कार्य मंत्री

भारत में शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। वर्तमान में शहरी कार्यबल का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है, जो शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इस अनौपचारिक क्षेत्र में पथ विक्रेताओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फल, सब्जियां, चाय, नाश्ता, कपड़े तथा दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले ये लाखों विक्रेता न केवल करोड़ों नागरिकों के जीवन को सुगम बनाते हैं, बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करते हैं। इसके बावजूद, लंबे समय तक उनकी औपचारिक बैंकिंग और ऋण तक पहुंच सीमित रही। क्रेडिट हिस्ट्री के अभाव में उन्हें अक्सर ऊंची ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण लेना पड़ता था, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो जाता था।

भारतीय पथ विक्रेता बदलती वैश्विक परिस्थितियों और विभिन्न आर्थिक व्यवधानों के बीच भी अपनी दृढ़ता और संघर्षशीलता के लिए जाने जाते हैं। पीएम स्वनिधि ने उनकी इस उद्यमशीलता को नई ऊर्जा प्रदान की है। यह केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सम्मान, पहचान और नए अवसरों का एक सशक्त माध्यम बनी है।

योजना की सफलता का प्रमुख आधार 'Whole of Government Approach' रहा, जिसमें केंद्र, राज्य, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकिंग संस्थानों के समन्वित प्रयासों ने इसे देशभर अभूतपूर्व रूप से पहुंचाया तथा उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किये।

इस योजना के अंतर्गत लाखों विक्रेताओं के बैंक खाते सक्रिय हुए, उनका वित्तीय व्यवहार दर्ज होने लगा और पहली बार उनके लिए एक औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री का निर्माण हुआ। इससे भविष्य में और अधिक ऋण तथा वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हुई और वे आज बैंक के सम्मानित ग्राहक और उद्यमी के रूप में उभरे हैं।

इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल सशक्तीकरण है। यूपीआई और क्यूआर-कोड आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इस पहल ने अभी तक 55 लाख विक्रेताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा, उनके लेन-देन को पारदर्शी बनाया और उनकी वित्तीय साख को मजबूत किया है।

योजना की सोच केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही। 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवारों को भारत सरकार की आठ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। अब तक 50 लाख से अधिक पथ विक्रेता परिवारों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत 1.52 करोड़ से अधिक लाभ स्वीकृत किए जा चुके हैं। पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर यह पहल पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का माध्यम बनी है।

इसके अतिरिक्त एफएसएसएआई के सहयोग से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं, जिससे विशेष रूप से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की गुणवत्ता, स्वच्छता और ग्राहक विश्वास में वृद्धि हुई है।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी योजना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। कुल लाभार्थियों में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे उनकी आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है।

वर्ष 2023 और 2025 में की गयी इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट अस्सेस्मेंट्स ने भी योजना के दूरगामी प्रभावों की पुष्टि की है। लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपने जीवन में पहली बार औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण प्राप्त किया, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इतना ही नहीं, बल्कि, लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी पीएम

'स्वनिधि से समृद्धि' पहल के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवारों को भारत सरकार की आठ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। अब तक 50 लाख से अधिक पथ विक्रेता परिवारों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत 1.52 करोड़ से अधिक लाभ स्वीकृत किए जा चुके हैं। पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर यह पहल पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का माध्यम बनी है

स्वनिधि से आगे बढ़कर अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त करने में सफल हुए, जो उनके बढ़ते वित्तीय विश्वास और सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल का प्रमाण है।

योजना के लाभार्थियों की आय में औसतन लगभग 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही आवास, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सुधार देखा गया है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच यूपीआई आधारित लेन-देन का उपयोग लगभग 45 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

योजना के व्यापक और सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगस्त, 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके पुनर्गठित स्वरूप को मार्च, 2030 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की।

पुनर्गठित योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के ऋण की सीमा में वृद्धि की गई है तथा योजना का दायरा शहरी स्थानीय निकायों से आगे बढ़ाकर Census Towns/Peri Urban तक विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही, क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि पथ विक्रेता बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उद्यमों को और अधिक सशक्त बना सकें। इसी क्रम में स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा पथ विक्रेताओं को उनकी तत्काल वित्तीय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालिक ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है।

पुनर्गठित योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के ऋण की सीमा में वृद्धि की गई है तथा योजना का दायरा शहरी स्थानीय निकायों से आगे बढ़ाकर Census Towns/ Peri Urban तक विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही, क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि पथ विक्रेता बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उद्यमों को और अधिक सशक्त बना सकें। इसी क्रम में स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा पथ विक्रेताओं को उनकी तत्काल वित्तीय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालिक ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है

यद्यपि, पीएम स्वनिधि योजना ने सड़क विक्रेताओं को वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान की है, फिर भी आज, कई जगह उन्हें शहर की नियोजन संरचना का हिस्सा नहीं माना जाता है। उन्हें सुनियोजित वेंडिंग स्थानों के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित स्थान न होने से उनकी आजीविका और ग्राहकों तक पहुंच प्रभावित होती है। इस चुनौती के समाधान हेतु आने वाले वर्षों में राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा पथ विक्रेताओं को शहरी नियोजन ढांचे का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दिशा में एक छोटी सी पहल— स्ट्रीट फूड हब के माध्यम से उन्हें सुगम एवं व्यवस्थित व्यापारिक स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल उनकी आजीविका अधिक सुदृढ़ होगी, बल्कि शहरों की स्वच्छता, सुव्यवस्था और समग्र शहरी वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत और 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करती है। पीएम स्वनिधि की सफलता इस बात का प्रमाण है कि समावेशी विकास का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है।

पीएम स्वनिधि योजना ने पथ विक्रेताओं के लिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह योजना लाखों विक्रेताओं की आजीविका को सशक्त बनाते हुए नई परिवर्तनकारी कहानियां रचेगी तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ■

लेख

भारत का सांस्कृतिक पुनरोद्धार काल

गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

भारत आज विकास के विभिन्न आयामों में तेज गति से प्रगति कर रहा है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भौतिक प्रगति के इन आयामों में आगे बढ़ते हुए यह भी आवश्यक है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति, इतिहास, धरोहर और विरासत को विस्मृत ना करें। भारत विश्व की प्राचीनतम जीवंत संस्कृतियों में से एक है, शताब्दियों तक विदेशी आक्रांताओं के साथ चले संघर्ष में देश में राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आता रहा, लेकिन भारत अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक स्थानांतरित करता रहा। इन वर्षों में हुई राजनीतिक उथल-पुथल में हमारे अनेक उपासना स्थल, ग्रंथ, पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों का विध्वंस किया गया, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपराएं फिर भी जीवित रहीं। सांस्कृतिक भारत पर दूसरी चोट हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने से हुई, जिसके द्वारा हमारे अंतर्मन में अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना उत्पन्न करने के प्रयास हुए।

वर्ष 2014 से भारत ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी एक बड़ी करवट ली, जिसे हम संस्कृति के पुनरोद्धार के आरंभ का वर्ष भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक भारत आज अपने गौरवशाली अतीत को पुनः स्मरण करते हुए उसके वैभव, उसकी भव्यता को ना सिर्फ पुनर्स्थापित कर रहा है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी वह संस्कृति पुनः स्थापित हो रही है। आज हमारे उत्सव, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, खान-पान, वस्त्र, कला, नृत्य, संगीत, शास्त्र, शिल्प वैश्विक आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं।

भारतीय संस्कृति की बढ़ती स्वीकार्यता

पिछले 12 वर्षों में विश्व में भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता बढ़ी है। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु यह प्राचीन भारतीय दर्शन है, जिसे विश्व ने मान्यता दी। मानव जीवन में उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसे अपनाया। आज विश्व के अनेक देशों से हमारी धरोहरें वापस देश में लौटीं हैं, जिनकी संख्या भी एक रोचक तथ्य है। वर्ष 2013 से पूर्व मात्र 13 धरोहरों को विदेशों से भारत लाया गया था, जबकि पिछले 12 वर्षों में 640 से अधिक धरोहरें विदेशों से भारत लौटी हैं। ये दर्शाता है कि संस्कृति में सिर्फ परंपराएं ही नहीं, अपितु संस्कृति के प्रतीक चिह्नों को वापस लाने के प्रति भी हमने गंभीरता दिखाई है। ये प्रतीक चिह्न हमारे लिए गौरव का विषय हैं, जो हमारे पूर्वजों की कला, शिल्प और विभिन्न विषयों के ज्ञान की निशानियां हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है।

दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे हमारे सामाजिक उत्सवों को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता मात्र उत्सवों को ही नहीं, अपितु इनके पीछे छुपे उन संदेशों को भी मिली है, जो बताती है कि असत्य पर सदैव सत्य की विजय होती है, बुराई हमेशा अच्छाई से पराजित होती है। हमारे प्राचीन इतिहास को भी आज यूनेस्को ने स्वीकारा है। उसका प्रमाण है कि भारत 44 विश्व धरोहर स्थलों के साथ ही विश्व में छटें और एशिया में दूसरे स्थान पर है। यह धरोहरें हमारी विरासत की प्रतीक हैं, जिन्हें देखकर भारतीयों को अपनी संस्कृति और इतिहास का परिचय मिलता है और उस पर गर्व होता है।

भूले और बिखरे ज्ञान का पुनर्संकलन

भारत एक लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं के साथ संघर्षरत रहा है। ज्ञान और संस्कृति का सम्मान न करने वाले इन विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के ज्ञान की अमूल्य विरासत रहे हमारे विश्वविद्यालय, गुरुकुल और पांडुलिपियों में लिखित ज्ञान को नष्ट करने के प्रयास किए। एक लंबे कालखंड में हमारी ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधि पांडुलिपियां विभिन्न मठों, मंदिरों, संस्थानों और घरों में संरक्षित की गईं, जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया। ये दुःख का विषय है कि स्वतंत्रता के बाद भी इन्हें संकलित कर प्राचीन ज्ञान को पुनः प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

आज विश्व के अनेक देशों से हमारी धरोहरें वापस देश में लौटीं हैं, जिनकी संख्या भी एक रोचक तथ्य है। वर्ष 2013 से पूर्व मात्र 13 धरोहरों को विदेशों से भारत लाया गया था, जबकि पिछले 12 वर्षों में 640 से अधिक धरोहरें विदेशों से भारत लौटी हैं। ये दर्शाता है कि संस्कृति में सिर्फ परंपराएं ही नहीं, अपितु संस्कृति के प्रतीक चिह्नों को वापस लाने के प्रति भी हमने गंभीरता दिखाई है। ये प्रतीक चिह्न हमारे लिए गौरव का विषय हैं

आज भारत में देश की प्राचीन संस्कृति के वाहक रहे काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक कॉरिडोर, केदारनाथ, सोमनाथ सहित विभिन्न मंदिरों और तीर्थनगरियों का व्यापक विकास किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए वहां सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति जागरुकता भी आई। आज इन स्थानों पर आने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या भारतीय संस्कृति के पुनरोत्थान का प्रतीक है

आज संपूर्ण देश में ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत इन पांडुलिपियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि समस्त भारत से अब तक 88 लाख से अधिक पांडुलिपियां प्राप्त हो चुकी हैं। इस ज्ञान को संकलित करने के साथ ही इन्हें आधुनिकतम तकनीक के साथ डिजिटाइज किया जा रहा है। इनमें लिखित ज्ञान को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में यह संकलन हमारी भावी पीढ़ियों को अध्यात्म, विज्ञान, कला, शिल्प जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्राचीन ज्ञान और उसकी उत्कृष्टता से परिचित कराएगा और उस पर गर्व करने को प्रेरित करेगा।

संस्कृति के प्रतीक चिह्नों का पुनरोत्थान

भारत के मंदिर, किले, मेले, ऐतिहासिक धरोहर स्थल हमारी गौरवशाली संस्कृति और इतिहास के प्रतीक चिह्न हैं। यह दुःख का विषय है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत के इन सांस्कृतिक स्थलों की उपेक्षा की गई। कुछ ही स्मारकों का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। यह मंदिर भारत की विविधता भरी संस्कृति को एक सूत्र में जोड़ कर रखते हैं। देश के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल वर्षों से उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार रहे। पिछले 12 वर्षों में इन स्थलों का कायाकल्प किया गया है। आज भारत में देश की प्राचीन संस्कृति के वाहक रहे काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक कॉरिडोर, केदारनाथ, सोमनाथ सहित विभिन्न मंदिरों और तीर्थनगरियों का व्यापक विकास किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए वहां सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति जागरुकता भी आई। आज इन स्थानों पर आने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या भारतीय संस्कृति के पुनरोत्थान का प्रतीक है। इन स्थानों के विकास और यहां की यात्राओं से युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का एहसास बढ़ा है।

विरासत भी, विकास भी

आज हमारी संस्कृति के प्रतीक चिह्न हमारे धार्मिक स्थल, मंदिर, धार्मिक मेले स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ ही इन नगरों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे लोगों की जीवनशैली में व्यापक सुधार हुआ है। आज ऋषिकेश, अयोध्या, प्रयागराज, काशी सहित भारत के विभिन्न आध्यात्मिक नगरों में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में भारतीय संस्कृति को जानने और समझने के लिए आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति की व्यापकता से अभिभूत हो रहे हैं। इससे न सिर्फ भारत की संस्कृति को प्रचार प्रसार मिल रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच रहा है।

जड़ों से जुड़ता भारत

आज भारत अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज भारत भूली, बिसरा दी गई अपनी संस्कृति के पुनर्जागरण का एक नया अध्याय लिख रहा है। अनेक शताब्दियों तक संघर्ष में उलझा रहा भारत एक नई करवट के साथ आज अपनी पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है। भारत आज विश्व को बता रहा है कि कैसे प्राचीन परंपरा और संस्कृति के साथ आधुनिकता को अपनाया जा सकता है, आने वाला समय नए भारत का है। भविष्य में भारत का विचार, भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति विश्व को नई दिशा देने जा रही है। ■

लेख

मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो किसान समृद्ध, गांव खुशहाल और देश सुखी रहेगा

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

भारत की आत्मा गांवों में और गांवों की आत्मा किसान में बसती है। किसान अन्नदाता होने के साथ ही प्रकृति और मानव जीवन के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले कुछ दशकों में देश की कृषि व्यवस्था ने उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया। इससे तत्काल उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरता, जल की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करने से भूमि की उत्पादकता घट रही है, खेती की लागत बढ़ रही है और किसान की आय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही।

ऐसे समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और 'धरती माता की सेहत बचाने' का दिया गया आह्वान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का राष्ट्रीय संकल्प है। राजस्थान जैसे विशाल कृषि प्रधान राज्य के लिए यह संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

राजस्थान की पहचान मरुस्थल के साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी कृषि और पशुपालन को जीवित रखने वाले मेहनतकश किसानों से है। यहां जल संकट, कम वर्षा, बढ़ती गर्मी और भूमि की क्षारीयता जैसी चुनौतियां पहले से मौजूद हैं। यदि ऐसे प्रदेश में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जारी रहा तो आने वाले वर्षों में मिट्टी की शक्ति और अधिक कमजोर हो सकती है। अब समय की मांग है कि किसान 'कम लागत, अधिक लाभ और स्वस्थ खेती' की दिशा में आगे बढ़ें।

हरित क्रांति के दौर में यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों को खेती का आधार माना गया। प्रारंभिक वर्षों में इससे उत्पादन बढ़ा, लेकिन लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों को असंतुलित कर दिया।

आज किसान को हर वर्ष पहले से अधिक खाद डालनी पड़ती है, फिर भी उत्पादन स्थिर रहता है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों ने खेती की लागत को बढ़ाया है। प्राकृतिक और जैविक विकल्प न केवल मिट्टी की सेहत सुधारते हैं, बल्कि लंबे समय में लागत घटाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण भूमि और जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं नागौर, सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में जल की सीमित उपलब्धता के कारण टिकाऊ खेती की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पर 'एक पेड़ मां के नाम' के साथ-साथ 'धरती मां को जहर से बचाने' की बात की है। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती, गौ आधारित कृषि, नैनो यूरिया, जैविक खाद और ड्रोन आधारित संतुलित छिड़काव जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से नैनो यूरिया ने किसानों के बीच नई आशा जगाई है। नैनो यूरिया कम मात्रा में अधिक प्रभावी साबित हो रहा है। इससे लागत भी घटती है और पर्यावरणीय नुकसान भी कम होता है।

राजस्थान में भी अब प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। अनेक किसान गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट और देसी बीजों की ओर लौट रहे हैं। कई गांवों में किसान समूह बनाकर जैविक उत्पादों का विपणन कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

खेती फसल उगाने के साथ मिट्टी, जल, पशुधन और पर्यावरण को संतुलित रखने की जीवन पद्धति है। आज दुनिया फिर उसी दिशा में लौट रही है। यूरोप और अमेरिका सहित अनेक देशों में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान के किसान इस अवसर को समझकर

प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पर 'एक पेड़ मां के नाम' के साथ-साथ 'धरती मां को जहर से बचाने' की बात की है। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती, गौ आधारित कृषि, नैनो यूरिया, जैविक खाद और ड्रोन आधारित संतुलित छिड़काव जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से नैनो यूरिया ने किसानों के बीच नई आशा जगाई है। नैनो यूरिया कम मात्रा में अधिक प्रभावी साबित हो रहा है। इससे लागत भी घटती है और पर्यावरणीय नुकसान भी कम होता है

वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं। राजस्थान के मोटे अनाज, बाजरा, मूंग, मैथी, जीरा और जैविक सब्जियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संभावनाएं रखती हैं।

राजस्थान में पशुधन की समृद्ध परंपरा रही है। यहां का ग्रामीण जीवन गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं से गहराई से जुड़ा रहा है। यदि पशुपालन और प्राकृतिक खेती को एक साथ जोड़ा जाए तो किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। गोबर और गौमूत्र आधारित खाद एवं जैविक घोल खेतों की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ रासायनिक निर्भरता कम कर सकते हैं।

किसानों के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि प्राकृतिक खेती उद्देश्य खेती को टिकाऊ, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक बनाना है। शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने पर उत्पादन स्थिर और बेहतर होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि खेती की लागत घटती है और किसान बाजार के महंगे रासायनिक उत्पादों पर कम निर्भर होता है।

हमारे बुजुर्गों ने सदियों तक धरती को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि मातृस्वरूप मानकर उसकी सेवा और संरक्षण किया। उन्होंने खेती करते हुए भूमि की उर्वरता, जैविक संतुलन और प्राकृतिक संपदा को सहेजकर अगली पीढ़ियों को सौंपा। आज हमारा भी यही दायित्व है कि हम रासायनिक अंधाधुंध उपयोग से बचते हुए मिट्टी की शक्ति, उसकी जीवंतता और प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध और उपजाऊ धरती मिल सके। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो भूमि को केवल संसाधन नहीं, बल्कि पूजनीय तत्व मानती है। अतः धरती की रक्षा करना हमारे लिए कर्तव्य के साथ पवित्र उपासना भी है।

यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो किसान समृद्ध रहेगा, गांव खुशहाल रहेंगे और देश सुखी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान वास्तव में 'स्वस्थ धरती, स्वस्थ किसान और स्वस्थ भारत' का मंत्र है। किसान भाइयों आइए, इस दिशा में आगे बढ़कर भावी पीढ़ियों के लिए उर्वर भूमि, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रसेवा होगी और यही भारतीय कृषि की स्थायी समृद्धि का मार्ग भी होगा। ■

प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि का किया वितरण

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मदद ने लाखों युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों और हितधारकों को संबोधित किया और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने तथा पूरे देश में रोजगार सृजन को तेज करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया, जो पीएम-वीबीआरवाई के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पीएम-वीबीआरवाई भारत सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रमुख प्रोत्साहन योजना है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार कर रही है। इस प्रोत्साहन से पूरे देश में रोजगार के 15 लाख अवसरो के सृजन में मदद मिली है।

श्री मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करने और उद्योग तथा कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए तैयार की गई एक पहल है।"

योजना की उपलब्धियों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 70 लाख नई नौकरियां सृजित की गई हैं और इतनी ही संख्या में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 20 लाख युवा पहली नौकरी में छह महीने पूरे कर चुके हैं, जबकि इस उपलब्धि को पूरा करने पर लगभग 10 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत पहले ही प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की गयी है।

श्री मोदी ने बताया कि सरकार का अवसंरचना में 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश रोजगार सृजन के लिए मजबूत आधार बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मदद ने लाखों युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया है। महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी विक्रेताओं और पारंपरिक कारीगरों की आजीविका को मजबूत किया है। ■

प्रधानमंत्री ने फ्रांस व स्लोवाकिया की सफल यात्रा की और जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर 13-18 जून के बीच फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की यात्रा की। 14 जून को श्री मोदी ने फ्रांस स्थित नीस में राष्ट्रपति श्री मैक्रों के साथ 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन किया तथा 14-15 जून को स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा की। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। स्लोवाकिया से श्री मोदी एवियन (फ्रांस) की यात्रा की, जहां उन्होंने 16-17 जून को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि यह लगातार आठवां जी-7 शिखर सम्मेलन था, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया। अंत में, श्री मोदी ने 18 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस की यात्रा की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति श्री मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 में भाग लिया। गौरतलब है कि विवाटेक यूरोप का प्रौद्योगिकी और नवाचार का सबसे बड़ा सम्मेलन है

फ्रांस यात्रा

फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून को नीस के विला केर्लियोस में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वर्ष की शुरुआत में भारत-फ्रांस संबंधों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक थी।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से

बातचीत की। उन्होंने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार पर संतोष व्यक्त किया तथा रक्षा प्लेटफॉर्मों और उन्नत तकनीकों के सह-डिज़ाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे और अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

'हॉराइजन 2047 रोडमैप' के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए दोनों नेताओं ने आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, टैलेंट मोबिलिटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए ठोस विचार भी साझा किए। द्विपक्षीय संबंधों में नवाचार और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस साझेदारी को दीर्घकालिक दिशा देने के लिए 'नवाचार रोडमैप 2030' को अपनाया।

मुख्य एमओयू/समझौता/घोषणा

- भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030 को अपनाना
- एआई शासन पर केंद्रित संयुक्त भारत-फ्रांस एआई कार्य समूह का गठन
- फ्रांस में भारत की रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) – के उपयोग की विस्तारित संभावनाएं
- स्टेशन एफ में अतिरिक्त 10 भारतीय स्टार्टअप्स का इनक्यूबेशन

प्रधानमंत्री ने 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम में लिया भाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों ने 14 जून को पैलेस डेस एक्सपोजिशन्स, नीस में संयुक्त रूप से 'भारत इनोवेट्स 2026' का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री मैक्रों का उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत और फ्रांस वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने वाले पुराने साझेदार रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भारत-फ्रांस की इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहलों और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों का जिक्र किया।

यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन 'वीवाटेक' में भागीदारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ 18 जून को पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन वीवाटेक 2026 में भाग लिया।

प्रौद्योगिकी उद्यमियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता

स्लोवाकिया यात्रा

स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम रॉबर्ट फिको के आमंत्रण पर भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जून को स्लोवाक गणराज्य का राजकीय दौरा किया। यह स्लोवाकिया को 1993 में स्वतंत्रता मिलने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इस देश का पहला दौरा था। इस तरह यह दौरा एक ऐतिहासिक पड़ाव होने के साथ ही दोनों राष्ट्रों के बीच चिरस्थाई मैत्री का एक नया मोड़ भी है। भारत और स्लोवाकिया ने 1993 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से पारंपरिक मैत्री और विश्वास, समानता तथा आपसी सम्मान के आधार पर बहुआयामी सहयोग विकसित किया है।

भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री इस दौरे की ऐतिहासिक प्रकृति और द्विपक्षीय सहयोग को गहराई देने की साझा प्रतिबद्धता की बुनियाद पर संबंध को आगे बढ़ाते हुए दोनों राष्ट्रों के बीच विस्तृत साझीदारी में तब्दील करने पर सहमत हुए। इस विस्तृत साझीदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना, सहयोग के मौजूदा तंत्र को मजबूती देना तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझीदारी को गहराई देने के नए अवसरों की तलाश करना है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बल

दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी के मुख्य स्तंभों रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। वे रक्षा प्रौद्योगिकियों, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक सहयोग के अवसर तलाशने के लिए अपने-अपने रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित परामर्श और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में नेताओं ने दोनों पक्षों के बीच 'रक्षा सहयोग पर आशय पत्र' पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया, जिससे रक्षा क्षेत्र में आपसी लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री को स्लोवाक गणराज्य के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित

एक विशेष समारोह में स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री पीटर पेलेग्रिनी ने 15 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी' से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। सम्मान स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 1.4 अरब लोगों तथा भारत और स्लोवाकिया के बीच कायम मैत्रीपूर्ण संबंधों को समर्पित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के लोगों को जोड़ने वाली गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह का प्रमाण बताते हुए आशा व्यक्त की कि यह सम्मान दोनों देशों की भावी पीढ़ियों को उनकी इस विशेष मित्रता को आगे भी बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। ■

(एआई) और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के विज़न तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के विस्तृत होते दायरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने भारत में व्यापक परिवर्तन संभव किए हैं, जिनमें डिजिटल भुगतान, एआई-सक्षम कृषि प्रगति से लेकर अत्याधुनिक स्पेस एप्लीकेशंस तक शामिल हैं। मुख्य संबोधन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने भारतीय स्टार्टअप्स तथा नवोन्मेषकों से संवाद किया, जो उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, सतत् विकास और गतिशीलता के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकियों एवं व्यावहारिक समाधानों का प्रदर्शन कर रहे थे।

जी-7 शिखर सम्मेलन एवियन (फ्रांस)

प्रधानमंत्री ने 'नई साझेदारियां बनाने और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करने' पर आयोजित सत्र को किया संबोधित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जून को फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन में 'नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना' विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में जहां ऊर्जा, भोजन, स्वास्थ्य, साइबर और आर्थिक सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हैं, मानवता की प्रगति और समृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बनाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में व्यापार और तकनीक का इस्तेमाल संकीर्ण

हितों के लिए किया जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसे की कमी पैदा हो रही है। कोविड महामारी से मिले सबक का उल्लेख करते हुए उन्होंने देशों से वैश्विक साझेदारियों में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाने पर ध्यान देने का आह्वान किया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत के नजरिए के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा 'मानवता सबसे पहले' के सिद्धांत का पालन किया है। यह सोच भारत की सभी कोशिशों के केंद्र में रही है, चाहे वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ या 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत काम करना हो। उन्होंने आगे कहा कि इसी समावेशी नजरिए की वजह से चाहे वह श्रीलंका में चक्रवात हो, अफ़गानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ या जमैका में तूफान हो, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है।

'इंश्योरिंग ए सेफ, रैपिड एंड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' विषय पर संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन में 'इंश्योरिंग ए सेफ, रैपिड एंड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी शक्ति है जिसमें मानव सभ्यता की दिशा को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है, लेकिन इसे लोगों को सशक्त बनाने वाला भी होना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि इसी व्यापक सोच के साथ भारत ने हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने हमेशा साइबरस्पेस को एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखा है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देशों के पास ऐसी एआई मॉडल तक पहुंच होनी चाहिए जो उनके महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को सुरक्षित कर सकें और उन्हें साइबर खतरों से निपटने में मदद कर सकें। उन्होंने एआई विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसमें सुरक्षा, गति और दक्षता पर एक साथ ध्यान दिया जाए।

वैश्विक नेताओं से बातचीत

अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे. ट्रम्प से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री ट्रम्प के उन प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने और व्यापक क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने पर एक सहमति बनी है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता और अबाधित वाणिज्य को बनाए रखने के महत्व तथा नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

दोनों नेताओं ने फरवरी, 2025 में वाशिंगटन डी.सी. में हुई अपनी बैठक के बाद से भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट (कॉम्पैक्टः कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी) के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, ऊर्जा और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्रों में हुई मुख्य प्रगति का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री की यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष हुई पारस्परिक यात्राओं के बाद से भारत-यूके संबंधों में आई मजबूत गति की समीक्षा की और 'विजन 2035' के सभी प्रमुख स्तंभों— व्यापार एवं आर्थिक विकास, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई एवं ग्रीन एनर्जी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तथा शिक्षा एवं लोगों के आपसी संबंधों— में हुई प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की।

यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जनवरी, 2026 में भारत में आयोजित ऐतिहासिक 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का स्मरण करते हुए नेताओं ने तब से भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का स्वागत किया। नेताओं ने हाल में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हुई वार्ता के सफल समापन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया तथा इस पर शीघ्र हस्ताक्षर और इसके त्वरित कार्यान्वयन पर बल दिया।

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ-साथ खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं और बहुलतावादी समाजों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के संबंध आपसी विश्वास, साझा मूल्यों तथा भविष्य के लिए समान विज़न पर आधारित हैं। नेताओं ने जनवरी, 2026 में अनुमोदित भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा तथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी एवं परिवर्तनकारी परिणाम सुनिश्चित करेगा।

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। वर्ष 2026 में दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी मुलाकात थी, जो भारत-यूएई की मजबूत और जीवंत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है।

दोनों नेताओं ने जनवरी, 2026 में राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा और मई, 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति तथा सकारात्मक घटनाक्रमों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। ■

प्रधानमंत्री ने रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने पर एक रैली को किया संबोधित

केंद्र सरकार का विज़न पूर्वी भारत के विकास के जरिये भारत का विकास है: नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून को मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पवित्र स्थलों 'संथाली जाहेरा' और 'हो जाहेरा में पूजा-अर्चना की तथा वे कौशल केंद्र और पहाड़पुर स्कूल देखने गये। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की थीम है 'विकास रा धारा, ओडिशा सारा'। श्री मोदी ने 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के दो साल पूरे होने पर ओडिशा के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "डबल-इंजन सरकार राज्य के विकास की गति को तेज कर रही है और कल्याणकारी योजनाओं, निवेश, औद्योगिक विकास व रोजगार के अवसरों के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला रही है।"

श्री मोदी ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि के निर्माता पंडित रघुनाथ मुर्मू, डॉ. दमयंती बेसरा और श्री चरण हेम्ब्रम सहित ओडिशा की प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने उनके मयूरभंज की मिट्टी से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक के सफर को ओडिशा और देश के लिए गर्व का विषय बताया।

उन्होंने केंद्र सरकार की 'भारत के विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास' की दृष्टि को दोहराया और जोर दिया कि 'पूर्वोदय' नीति पूर्वी राज्यों की विशाल संभावनाओं को सामने ला रही है। श्री मोदी ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकारें रेलवे अवसंरचना, राजमार्ग, आर्थिक कॉरिडोर, पत्तन, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और आधुनिक उद्योगों में रिकॉर्ड निवेश के जरिए इन ताकतों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लगभग 47,000 करोड़ रुपये की परिवर्तनकारी परियोजनाएं ओडिशा के लोगों के लिए परिवहन-संपर्क, सार्वजनिक सेवाओं, आर्थिक अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार लाएंगी। ओडिशा पूर्वी भारत में विकास और समृद्धि के प्रवेश-द्वार के रूप में उभर रहा है और राज्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ओडिशा के प्रचुर संसाधनों को विकास और समृद्धि के अवसरों में बदल रही है। उन्होंने 'उत्कर्ष ओडिशा' जैसी पहलों का ज़िक्र किया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और पूरे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने कहा, "इस पहल के तहत ओडिशा ने पहले ही लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं, जबकि कई बड़ी परियोजनाएं, जिनकी लागत 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, वर्तमान में कार्यान्वयन-चरण में हैं। राज्य के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।"

पीएम जनमन मिशन

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन मिशन राष्ट्रपति मुर्मु के साथ हुई चर्चाओं से उभरा और यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए डिजाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं सीधे सबसे वंचित जनजातीय समुदायों के दरवाजे तक पहुंचें।

जनजातीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों के महत्व पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 750 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा जनजातीय छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर सैकड़ों करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मिली है। ■

पश्चिम बंगाल विकास और राष्ट्र-निर्माण की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून को 'पश्चिमबंग दिवस' (पश्चिम बंगाल दिवस) समारोह में भाग लिया। इस राज्य-स्तरीय समारोह का आयोजन हुगली के तारकेश्वर में किया जा रहा है, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इस वर्ष के पश्चिमबंग दिवस का मुख्य विषयः 'पश्चिम बंगालः विरासत, सद्भाव और विकास' है। यह राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकजुटता और विकास की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से जुड़ी ये परियोजनाएं अवसंरचना को मजबूत करेंगी, आजीविका में सुधार करेंगी, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देंगी और पूरे राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देंगी।

पीएम-किसान की 23वीं किस्त जारी

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 23वीं किस्त भी जारी की। इस किस्त के तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई।

प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हाल ही में हुए चुनावों और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद राज्य का यह उनका पहला दौरा था। पश्चिम बंगाल और देश की जनता का अभिवादन करते हुए श्री मोदी ने इस अवसर को एक ऐतिहासिक पल बताया, जो पूरे राज्य में नई उम्मीद, आत्मविश्वास और प्रगति की भावना को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा, "पश्चिम बंगाल विकास और राष्ट्र-निर्माण की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। लोगों में दिख रहा उत्साह और राज्य का सकारात्मक माहौल एक उज्ज्वल भविष्य के प्रति बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।"

उन्होंने 'स्वच्छता से स्वागत' पहल में हिस्सा लेने के लिए नागरिकों को बधाई दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वच्छता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी और संवहनीय विकास का अहम हिस्सा बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया, जिन्होंने विभाजन के समय बंगाल का एक हिस्सा भारत के पास बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। श्री मोदी ने कहा, "रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी महान हस्तियों से समृद्ध पश्चिम बंगाल की विरासत देश को प्रेरित करती आ रही है। इस विरासत को संजोने और इसका जश्न मनाने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसर पैदा करने की भी ज़रूरत है।"

श्री मोदी ने कहा कि नई सरकार ने दशकों से जमा हो रही चुनौतियों का समाधान करना शुरू कर दिया है और विकास की गति बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए तेज़ी से फ़ैसले लिए जा रहे हैं और लंबे समय से पड़ी लंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल की जनता से किए गए वादे तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के हर जरूरतमंद गरीब परिवार को अब 'आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा' योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, जल जीवन मिशन के ज़रिए साफ़ पेयजल तक बेहतर पहुंच, सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में छूट और महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा लागू करने का भी ज़िक्र किया। श्री मोदी ने कहा, "जो कल्याणकारी योजनाएं बरसों से अटकी हुई थीं, वे अब जन-संपर्क शिविरों के ज़रिए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित हो रही है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है।" ■

एवियन (फ्रांस) में 16 जून, 2026 को जी–7 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नीस (फ्रांस) में 14 जून, 2026 को 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

एवियन (फ्रांस) में 17 जून, 2026 को जी–7 शिखर सम्मेलन–2026 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ब्रातिस्लावा में 14 जून, 2026 को स्लोवाकिया आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करता भारतीय समुदाय

ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया) में 15 जून, 2026 को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री श्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 25 जून, 2026
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

भारत की संस्कृति

आज मजबूती से आगे बढ़ रही है

'विरासत भी, विकास भी' ने विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण को नया आकार दिया: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विरासत भी, विकास भी' के दृष्टिकोण ने भारत की विकास यात्रा के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह बदल दिया है। यह आंदोलन केवल स्मारकों को बचाने का नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यतागत पहचान पर गर्व करने और विरासत को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का भी है। भारत 668 से अधिक चोरी हुई प्राचीन कलाकृतियों को वापस लाने में कामयाब हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर जैसे आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और भारतीय परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास निरंतर जारी है। साथ ही, पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने, तीर्थयात्रा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और पर्यटन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के बड़े प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित भी रहे।

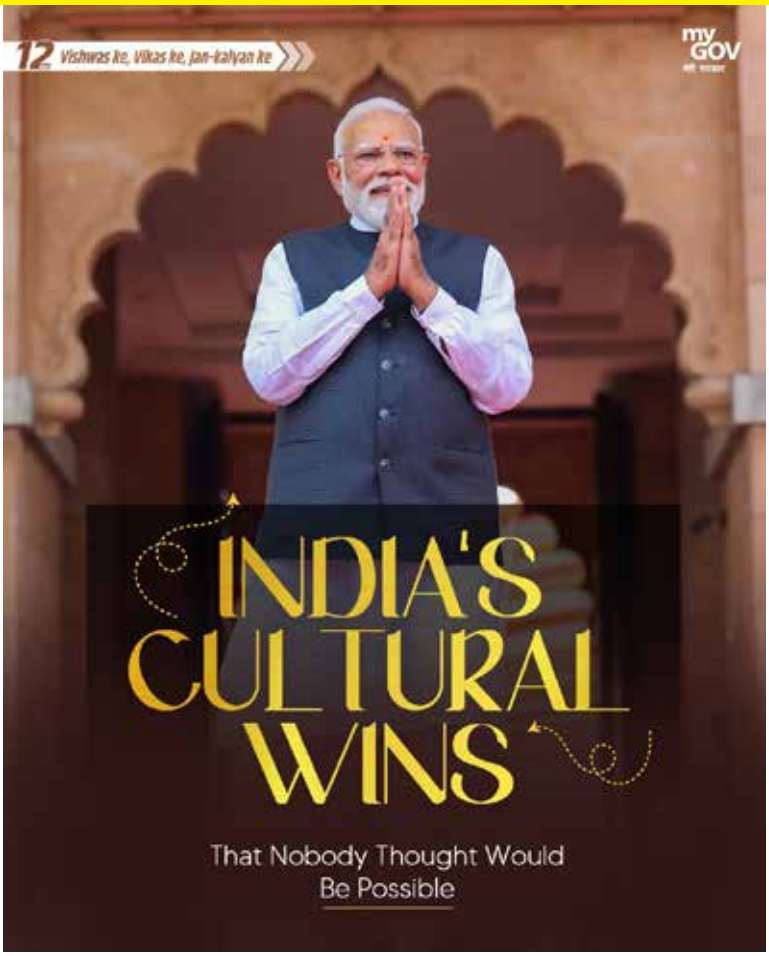

छायाकार: अजय कुमार सिंह